



राजस्थान शासन

आय-व्ययक एक दृष्टि में Budget At A Glance 2026-27



Government of Rajasthan

आय व्ययक एक दृष्टि में BUDGET AT A GLANCE 2026-27

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर

Directorate of Economics and Statistics,
Statistics Department, Rajasthan, Jaipur

विषय सूची

Table of Contents

1	परिचय एवं मुख्य परिभाषाएं Introduction & Important Definitions	1 40
2	आय व्ययक एक दृष्टि में Budget at a Glance	2 41
3	प्राप्तियां Receipts	5 44
4	व्यय Expenditure	8 47
5	कृषि बजट Agriculture Budget	10 49
6	अनुसूचित जनजाति उप-योजना बजट Scheduled Tribal Sub Plan Budget	11 50
7	अनुसूचित जाति उप-योजना बजट Scheduled Caste Sub Plan Budget	12 51
8	जेंडर बजट Gender Budget	13 52
9	चाइल्ड बजट Child Budget	14 53
10	ग्रीन बजट Green Budget	15 54
11	योजनाओं के उद्ब्यय के मुख्य बिन्दु Highlights of Schematic Outlay	16 55
12	क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं Sectorwise Highlights	17 56

आय व्ययक एक दृष्टि में

परिचय

बजट एक दृष्टि में बजट की सम्पूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया है कि इन्हें आसानी से समझा जा सके। इस दस्तावेज में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ राजकोषीय घाटा (एफडी), राजस्व घाटा (आरडी), और प्राथमिक घाटा (पीडी) दर्शाया गया है। ग्राफ और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से प्राप्तियों के स्रोतों और उनके व्यय का चित्रात्मक ब्यौरा दिया गया है।

मुख्य परिभाषाएं

राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का कर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा, गैर कर राजस्व तथा केन्द्रीय सहायता शामिल है।

राज्य का स्वयं का कर राजस्व - विधि द्वारा स्थापित किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अंतर्गत राज्य द्वारा वसूला गया कर स्वयं का कर राजस्व कहलाता है।

केन्द्रीय करों में हिस्सा - संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानुसार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य को हस्तान्तरित राशि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा है।

गैर कर राजस्व - राज्य सरकार के विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं से प्राप्त उपयोगिता प्रभार, फीस, रायल्टी, पेनल्टी, ब्याज प्राप्तियाँ आदि से प्राप्त राजस्व गैर कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

केन्द्रीय सहायता - केन्द्र सरकार से वित्त आयोग की अभिशंषानुसार प्राप्त सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में केन्द्र का अंशदान तथा विविध प्राप्तियाँ जो कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में होती हैं, केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदर्शित हैं।

राजस्व व्यय - राजस्व व्यय का अर्थ अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव और कार्यचालन व्यय के लिए सभी शुल्क हैं, जो आस्तियों को एक चलते क्रम में बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं और साथ ही कार्यालय और प्रशासनिक खर्चों सहित दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्च भी शामिल हैं।

पूंजीगत परिव्यय - भविष्य के लाभों को बनाने के लिए किया गया व्यय जैसे भूमि, भवन, मशीनें, मौजूदा सुविधाओं या परिसम्पत्तियों का उन्नयन, और इसमें सरकार द्वारा शेयरों में किए गए निवेश भी शामिल हैं।

राजस्व घाटा - किसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना राजस्व घाटे की स्थिति दर्शाता है। राजस्व घाटे के लिए ऋणात्मक आंकड़ा राजस्व आधिक्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है।

राजकोषीय घाटा - राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटा - किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला जाता है। प्राथमिक घाटा कुल व्यय में से ब्याज भुगतान को छोड़कर शेष व्यय हेतु वांछित शुद्ध उधार की राशि को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे का ऋणात्मक आंकड़ा प्राथमिक आधिक्य की स्थिति दर्शाता है।

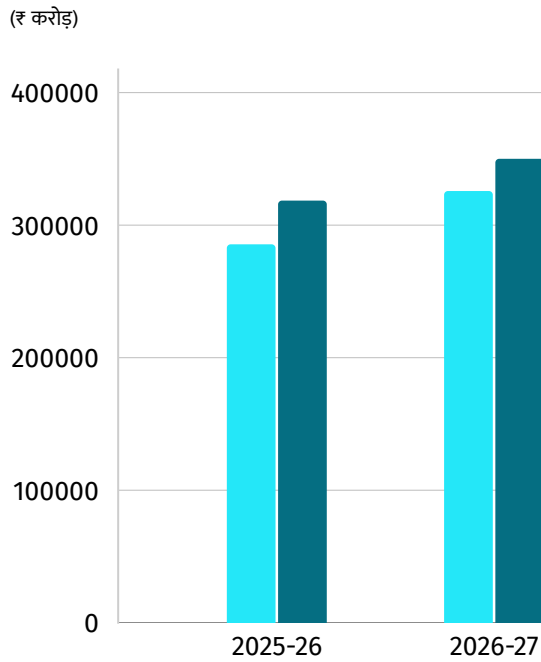
आय व्ययक एक दृष्टि में

(₹ लाख)

क्र.सं.	विवरण	संशोधित अनुमान 2025-26	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
1	कुल प्राप्तियां	55868198.66	61117400.07
1A	राजस्व प्राप्तियां	28553334.34	32574013.55
1B	पूंजीगत प्राप्तियां	27314864.32	28543386.52
1B(i)	जिसमें से गैर ऋण प्राप्तियां	144618.20	39980.98
2	कुल व्यय	55859615.59	61095630.01
2A	राजस्व व्यय	31851625.73	35005407.08
2A(i)	जिसमें से ब्याज भुगतान	4296067.76	4367521.93
2B	पूंजीगत व्यय (खाता)	24007989.86	26090222.93
2B(i)	जिसमें से पूंजीगत परिव्यय	3942917.44	5397841.08
2B(ii)	ऋण एवं अग्रिम	152671.37	159998.78
3	राजस्व घाटा (2A-1A)	3298291.39	2431393.53
4	बजट आधिक्य (1-2)	8583.07	21770.06
5	राजकोषीय घाटा $[(2A+2B(i))+2B(ii)-(1A+1B(i))]$	7249262.00	7949252.41
6	प्रारम्भिक घाटा $[5-2A(i)]$	2953194.24	3581730.48

आय व्ययक एक दृष्टि में

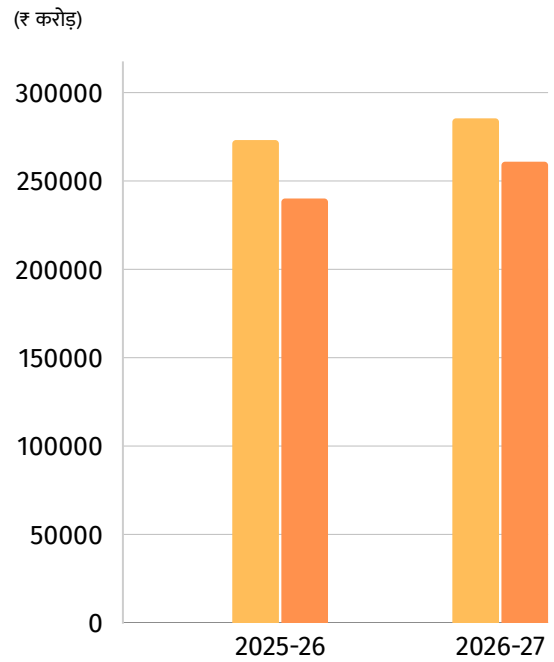
राजस्व



राजस्व प्राप्तियां

राजस्व व्यय

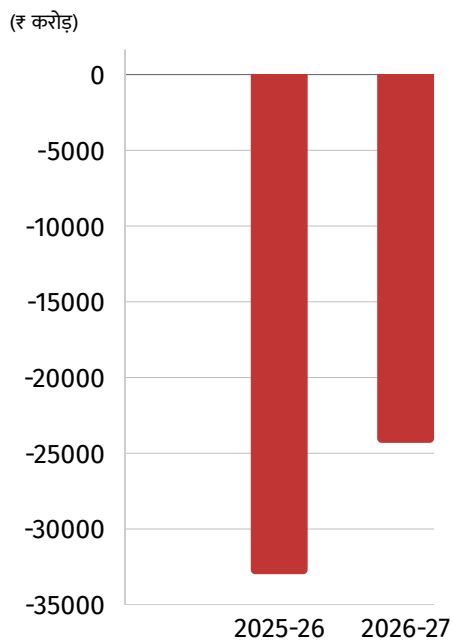
पूंजीगत



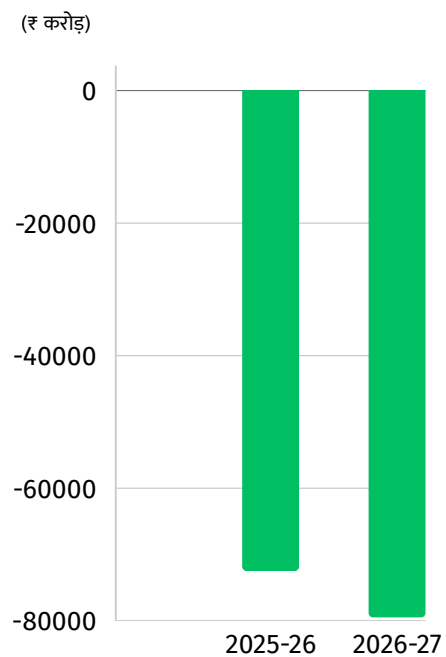
पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत व्यय (खाता)

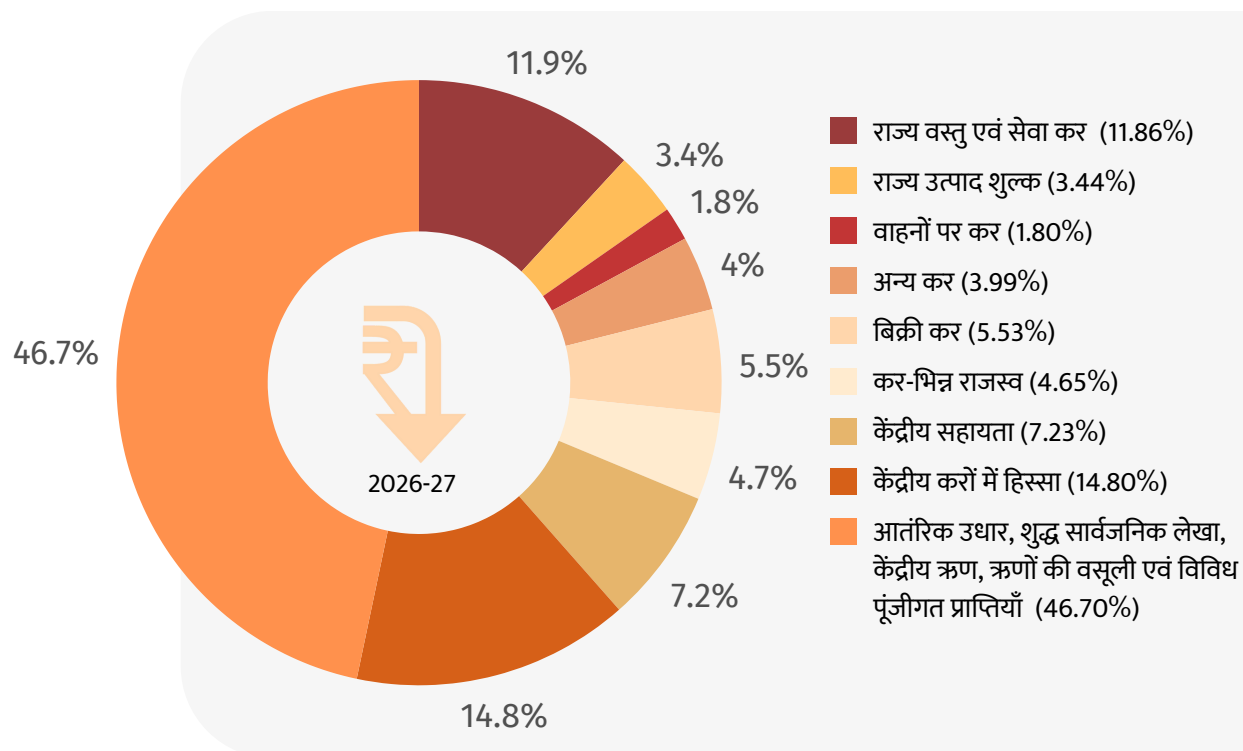
राजस्व घाटा (-)



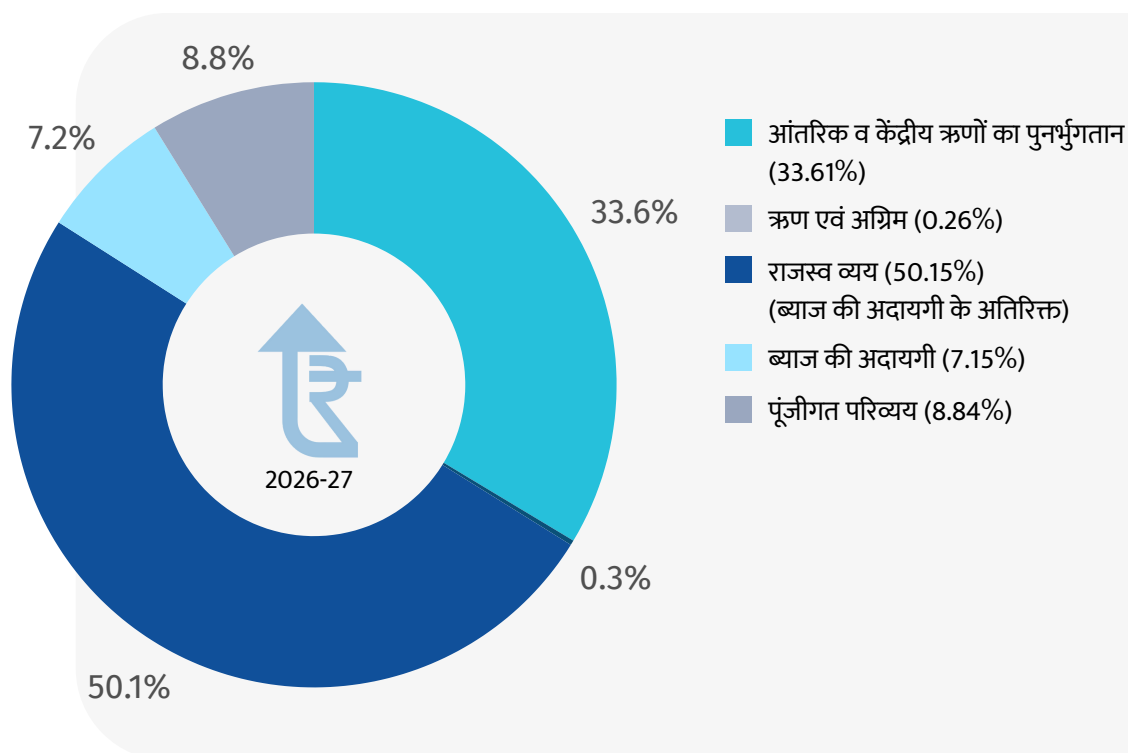
राजकोषीय घाटा (-)



रुपया आता है



रुपया जाता है



प्राप्तियां

(₹ लाख)

क्र.सं.	विवरण	संशोधित अनुमान 2025-26	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
1	स्वयं का कर राजस्व	13853935.91	16266847.42
i	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	6170000.00	7250000.00
ii	भू-राजस्व	176130.50	178145.52
iii	मुद्रांक एवं पंजीयन	1500000.00	1875000.00
iv	राज्य उत्पाद शुल्क	1900000.00	2100000.00
v	बिक्री कर	2800000.00	3380000.00
vi	वाहनों पर कर	960000.00	1100000.00
vii	विद्युत पर कर तथा शुल्क	342500.00	378500.00
viii	अन्य कर एवं शुल्क	5305.41	5201.90
2	केंद्रीय करों में हिस्सा	8394045.00	9044585.00
i	वस्तु एवं सेवा कर	2363483.00	2473689.00
ii	आयकर	2969533.00	3218725.00
iii	निगम कर	2477818.00	2655056.00
iv	संघ उत्पादन शुल्क	124913.00	205569.00
v	सीमा शुल्क	451333.00	482556.00

क्रमशः

प्राप्तियां

(₹ लाख)

क्र.सं.	विवरण	संशोधित अनुमान 2025-26	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
vi	सेवा कर	-293.00	0.00
vii	अन्य कर	7258.00	8990.00
3	कर भिन्न राजस्व	2514307.76	2843479.26
i	खनिज	1178000.00	1372500.00
ii	पेट्रोलियम	210000.00	230000.00
iii	ब्याज प्राप्तियां	269711.69	309735.26
iv	अन्य कर भिन्न राजस्व	856596.07	931244.00
4	केंद्रीय सहायता	3791045.67	4419101.87
5	कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	28553334.34	32574013.55
6	पूंजीगत प्राप्तियां	27314864.32	28543386.52
i	उधार एवं अग्रिम की वसूली	143618.20	38980.98
ii	आन्तरिक ऋण	25050587.82	25768896.04
iii	केंद्रीय सरकार से लिया गया ऋण	1203653.01	1765144.01
iv	शुद्ध सार्वजनिक लेखा	916005.29	969365.49
v	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	1000.00	1000.00
7	कुल प्राप्तियां (5+6)	55868198.66	61117400.07

प्राप्तियां

2026-27



व्यय

(₹ लाख)

क्र.सं.	विवरण	संशोधित अनुमान 2025-26	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
I	राजस्व व्यय	31851625.73	35005407.08
i	सामान्य सेवाएं	9911143.43	10426903.14
ii	सामाजिक सेवाएं	13379069.71	14331432.77
iii	आर्थिक सेवाएं	8561408.14	10247071.16
iv	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	4.45	0.01
II	पूंजीगत व्यय	24007989.86	26090222.93
1	पूंजीगत परिव्यय	3942917.44	5397841.08
i	सामान्य सेवाएं	91326.78	149182.54
ii	सामाजिक सेवाएं	1617646.76	2689219.73
iii	आर्थिक सेवाएं	2233943.90	2559438.81
2	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	19912401.05	20532383.07
3	ऋण एवं अग्रिम	152671.37	159998.78
	कुल व्यय	55859615.59	61095630.01

व्यय

2026-27

ऋण एवं अग्रिम
₹1599.99
करोड़

राजस्व व्यय
₹350054.07
करोड़

कुल व्यय
₹6,10,956.30 करोड़

पूँजीगत परिव्यय
₹53,978.41
करोड़

लोक ऋण का
पुनर्भुगतान
₹2,05,323.83
करोड़



कृषि बजट

कृषि, कृषक कल्याण एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर कुल व्यय

(₹ लाख)

क्र.सं.	क्षेत्र	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
1	कृषि सब्सिडी (विद्युत अनुदान, ब्याज अनुदान, गौशालाओं आदि को अनुदान)	4219110.74
2	कृषि साख (किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण)	2548000.02
3	बाँध, नहरें, कृषि कनेक्शन एवं अन्य आधारभूत संरचना विकास	1813207.06
4	कृषि बीमा (फसल एवं पशु बीमा आदि)	598793.19
5	सामाजिक सुरक्षा (मनरेगा, लघु एवं सीमान्त किसानों को पेंशन आदि)	703982.91
6	कृषि उपज मण्डी समिति	900170.51
7	कृषि शासकीय व्यवस्था	491501.34
8	कृषि आधारित अन्य गतिविधियां	484707.28
9	कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा कौशल विकास	181338.44
	कुल योग	11940811.48



अनुसूचित जनजाति उप-योजना बजट

अनुसूचित जनजाति उप-योजना में योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधान

(₹ लाख)

क्र.सं.	क्षेत्र	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
1	कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण	222742.20
2	स्वास्थ्य एवं कल्याण	375686.33
3	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	550058.38
4	सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	472727.15
5	औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	88008.93
6	पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	4468.72
7	आधारभूत अवसंरचना	766066.17
8	जल सुरक्षा एवं अनुकूलता	293920.69
9	पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	29782.49
10	ग्रामीण विकास	509259.93
11	शहरी विकास	252792.29
12	प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं	32666.31
13	वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति	20193.67
	कुल योग	3618373.26



अनुसूचित जाति उप-योजना बजट

अनुसूचित जाति उप-योजना में योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधान

(₹ लाख)

क्र.सं.	क्षेत्र	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
1	कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण	285077.27
2	स्वास्थ्य एवं कल्याण	525378.99
3	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	682541.28
4	सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	525806.92
5	औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	100562.50
6	पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	4785.11
7	आधारभूत अवसंरचना	1238006.40
8	जल सुरक्षा एवं अनुकूलता	246535.30
9	पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	46535.71
10	ग्रामीण विकास	593542.11
11	शहरी विकास	348420.42
12	प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं	37167.22
13	वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति	65260.01
	कुल योग	4699619.24



जेंडर बजट

महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान

(₹ लाख)

क्र.सं.	क्षेत्र	आय-व्ययक अनुमान 2026-27 (श्रेणी 'अ'- 70 प्रतिशत एवं अधिक प्रावधान वाले विशिष्ट क्षेत्रों का विवरण)	आय-व्ययक अनुमान 2026-27 (श्रेणी 'ब'- 70 प्रतिशत से कम प्रावधान वाले विशिष्ट क्षेत्रों का विवरण)
1	कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण	6425.00	144365.49
2	स्वास्थ्य एवं कल्याण	162018.93	1053368.12
3	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	204253.94	1688490.82
4	सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	759260.57	852715.91
5	औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	-	61589.47
6	पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	-	7957.50
7	आधारभूत अवसंरचना	-	1665025.43
8	जल सुरक्षा एवं अनुकूलता	-	17573.95
9	पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	-	114.01
10	ग्रामीण विकास	93582.53	632626.11
11	शहरी विकास	-	39820.51
12	प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं	6412.96	35621.54
	कुल योग	1231953.93	6199268.88



चाइल्ड बजट

18 वर्ष तक के बालक / बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकास से संबन्धित क्षेत्रों में किए गए प्रावधान का विवरण

(₹ लाख)

क्र.सं.	क्षेत्र	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
1	स्वास्थ्य एवं कल्याण	8616.13
2	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	4326667.71
3	सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	778498.43
	कुल योग	5113782.27



ग्रीन बजट

पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रीन ग्रोथ के लिए योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान

(₹ लाख)

क्र.सं.	क्षेत्र	आय-व्ययक अनुमान 2026-27
1	कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण	530564.39
2	स्वास्थ्य एवं कल्याण	20527.01
3	शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था	20807.18
4	सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन	6318.30
5	औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	4270.05
6	पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास	188.54
7	आधारभूत अवसंरचना	854575.31
8	जल सुरक्षा एवं अनुकूलता	776346.81
9	पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता	189716.65
10	ग्रामीण विकास	683437.79
11	शहरी विकास	163566.00
12	प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं	97227.74
13	वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति	7.06
	कुल योग	3347552.83

योजनागत प्रावधानों के मुख्य बिन्दु 2026-27

2,62,781.58 करोड़



कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

14398.20 करोड़

5.48%



स्वास्थ्य एवं कल्याण

27069.37 करोड़

10.30%



शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

46017.40 करोड़

17.51%



सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन

28489.35 करोड़

10.84%



औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि

6441.07 करोड़

2.45%



पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

509.92 करोड़

0.19%



आधारभूत अवसंरचना

58460.44 करोड़

22.25%



जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

17220.30 करोड़

6.55%



पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

4536.64 करोड़

1.73%



ग्रामीण विकास

33418.86 करोड़

12.72%



शहरी विकास

20323.61 करोड़

7.73%



प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं

3799.98 करोड़

1.45%



वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

2096.44 करोड़

0.80%

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

1. कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपान्तरण



कृषि विभाग के लिए ₹4,147.51 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है :

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए राज्य निधि से राशि ₹2,298.71 करोड़।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए ₹252.14 करोड़ (राज्यांश ₹98.65 करोड़ सहित)।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिए ₹200.00 करोड़ (राज्यांश ₹79.99 करोड़ सहित)।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए ₹210.00 करोड़ (राज्यांश ₹84.00 करोड़ सहित)।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹80.06 करोड़ (राज्यांश ₹32.02 करोड़ सहित)।
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए ₹72.23 करोड़ (राज्यांश ₹28.89 करोड़ सहित)।
- राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिए ₹61.70 करोड़ (राज्यांश ₹24.68 करोड़ सहित)।
- परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए ₹59.59 करोड़ (राज्यांश ₹25.14 करोड़ सहित)।
- मिशन फॉर आत्म निर्भरता इन पल्सेस के लिए ₹274.19 करोड़ (राज्यांश ₹104.47 करोड़ सहित)।



उद्यानिकी विभाग के लिए ₹1,596.71 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है

- सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए ₹600.00 करोड़ (राज्यांश ₹240.00 करोड़ सहित)।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक-ब) के लिए राज्य निधि से ₹400.13 करोड़।
- सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु राज्य निधि से ₹300.00 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए ₹149.90 करोड़ (राज्यांश ₹59.96 करोड़ सहित)।



पांच कृषि विश्वविद्यालयों के लिए ₹390.08 करोड़ का प्रावधान



कृषि विपणन के लिए ₹750.76 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है

- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विकास योजनाओं के लिये सहायता राज्य निधि से ₹350.00 करोड़।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिये ₹45.96 करोड़ (राज्यांश ₹18.38 करोड़ सहित)।



पशुपालन विभाग के लिए ₹1,308.62 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है

- पशु अस्पताल और औषधालयों के लिए राज्य निधि से ₹674.94 करोड़।
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए राज्य निधि से ₹100.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिए राज्य निधि से ₹103.48 करोड़।



पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए ₹91.33 करोड़



गोपालन विभाग के लिए ₹2,609.18 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है

- गौशालाओं के लिए राज्य निधि से ₹1,400.00 करोड़ का अनुदान।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिए राज्य निधि से ₹700.00 करोड़।
- नंदीशाला योजना के लिए राज्य निधि से ₹27.00 करोड़।



सहकारिता विभाग के लिए ₹3,374.50 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिये राज्य निधि से ₹1,973.83 करोड़।
- सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान के लिए राज्य निधि से ₹700.00 करोड़।
- सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिए राज्य निधि से ₹465.00 करोड़।



जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण के लिए राज्य निधि से ₹75.74 करोड़ का प्रावधान



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य

- खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल - 162.25 लाख हैक्टेयर
- खाद्यान्नों का उत्पादन - 283.15 लाख मै. टन
- तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल - 67.02 लाख हैक्टेयर
- तिलहन का उत्पादन - 111.05 लाख मै. टन
- गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल - 0.05 लाख हैक्टेयर
- गन्ना उत्पादन - 4.05 लाख मै. टन
- कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल - 7.50 लाख हैक्टेयर
- कपास उत्पादन - 28.73 लाख गांठें
- कृत्रिम गर्भाधान - 38.66 लाख
- बंध्याकरण - 10.08 लाख
- मत्स्य उत्पादन - 1,17,000 मेट्रिक टन
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक-बी) अन्तर्गत 50,000 सोलर सिस्टम की स्थापना।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) के अन्तर्गत 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना करना।
- विभिन्न फसलों (बाजरा, मूंग, ज्वार, मक्का, मोठ एवं सरसों) के लिए 07 लाख किसानों को मिनी किट का निःशुल्क वितरण।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 71.83 लाख किसानों को लाभाविन्त करना।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

2. स्वास्थ्य एवं कल्याण

स्वास्थ्य



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 12,195.81 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित है

- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए राज्य निधि से ₹3,000.00 करोड़।
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021 के लिए राज्य निधि से ₹3,817.09 करोड़।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के लिए राज्य निधि से ₹1,548.92 करोड़।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राज्य निधि से ₹1,062.00 करोड़।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राज्य निधि से ₹686.16 करोड़।
- उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राज्य निधि से ₹271.93 करोड़।
- नाबार्ड सहायित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण के लिए राज्य निधि से ₹250.00 करोड़।



राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए ₹ 4,853.56 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है

- राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए ₹3,392.62 करोड़ (राज्यांश ₹1,357.05 करोड़ सहित)।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिये ₹876.20 करोड़ (राज्यांश ₹350.48 करोड़ सहित)।



परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹1,798.08 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं

- ग्रामीण उपकेन्द्र के लिए ₹1,046.36 करोड़ (राज्यांश ₹98.41 करोड़ सहित)।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीका करण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये राज्य निधि से ₹335.50 करोड़।
- जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के लिए ₹193.17 करोड़ (राज्यांश ₹135.07 करोड़ सहित)।
- शहरी परिवार कल्याण केन्द्र के लिए ₹127.60 करोड़ (राज्यांश ₹83.95 करोड़ सहित)।



चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ₹2,995.46 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए ₹1,541.23 करोड़ (राज्यांश ₹740.43 करोड़ सहित)।
- राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी के लिए राज्य निधि से ₹ 1,123.50 करोड़।



चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के लिए ₹865.42 करोड़ का प्रावधान (राज्यांश ₹842.94 करोड़ सहित)।

चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर के लिए राज्य निधि से ₹461.63 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर के लिए ₹333.69 करोड़ का प्रावधान (राज्यांश ₹313.40 करोड़ सहित)।

चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा के लिए ₹341.50 करोड़ का प्रावधान (राज्यांश ₹325.34 करोड़ सहित)।

चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर के लिए ₹345.02 करोड़ का प्रावधान (राज्यांश ₹290.44 करोड़ सहित)।

चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर के लिए ₹276.97 करोड़ का प्रावधान (राज्यांश ₹239.44 करोड़ सहित)।



आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के लिए ₹787.67 करोड़ का प्रावधान (राज्यांश ₹553.67 करोड़ सहित)।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए राज्य निधि से ₹10.50 करोड़ का प्रावधान।



आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के लिए ₹52.24 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए ₹33.20 करोड़ का प्रावधान।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए ₹1,750.24 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित है:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ₹586.02 करोड़ (राज्यांश ₹348.12 करोड़ सहित) का प्रावधान।
- रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लिए ₹900.00 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान कृषक समर्थन योजना के लिए ₹245.00 करोड़ का प्रावधान।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजनान्तर्गत 1.37 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
- 05 जिला चिकित्सालयों, 15 उपजिला चिकित्सालयों, 03 माँ शिशु चिकित्सालयों, 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 03 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 38 ट्रोमा केन्द्र, 03 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 47 उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 09 सैटेलाइट चिकित्सालय के भवनों का निर्माण।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) अन्तर्गत 20 करोड़ रोगियों को लाभान्वित।
- राजमेस के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में 120 यूजी सीट्स और 235 पीजी सीट्स की अभिवृद्धि।
- आरयूएचएस डेन्टल कॉलेज में 50 बीडीएस सीट्स की अभिवृद्धि।
- राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय 370 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन।
- राज्य एवं संभाग स्तरीय 07 आरोग्य मेलों का आयोजन।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

- रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजनान्तर्गत 1.08 करोड़ एनएफएसए परिवारों को लाभान्वित करना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.47 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित करना।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

3. शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

शिक्षा के लिए ₹46,017.40 करोड़ का प्रावधान।

शिक्षा



प्रारम्भिक शिक्षा के लिये ₹21,646.29 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के लिए ₹13,767.54 करोड़ (राज्यांश ₹9,745.11 करोड़ सहित)।
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायतीराज विभाग के माध्यम से राज्य निधि से ₹5,653.15 करोड़।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण (RTE) के लिए ₹1,250.00 करोड़ (राज्यांश ₹919.46 करोड़ सहित)।
- समग्र शिक्षा - स्टार परियोजना के लिए ₹91.61 करोड़ (राज्यांश ₹37.24 करोड़ सहित)।
- पी.एम. श्री योजना के लिये ₹434.67 करोड़ (राज्यांश ₹173.87 करोड़ सहित)।
- राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिए ₹150.00 करोड़ (राज्यांश ₹81.00 करोड़ सहित)।



मिड-डे-मील के लिए ₹2,091.80 करोड़ का प्रावधान जिसमें पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के राज्य निधि से ₹798.00 करोड़ सम्मिलित तथा पीएम पोषण योजना के लिए ₹1,293.80 करोड़ (राज्यांश ₹592.52 करोड़ सहित)।



माध्यमिक शिक्षा के लिये राशि ₹19,473.51 करोड़ प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- माध्यमिक विद्यालयों के लिए राज्य निधि से ₹14,842.79 करोड़।
- समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के लिए ₹2,821.63 करोड़ (राज्यांश ₹1,588.36 करोड़ सहित)।
- खण्ड स्तर पर उच्च गुणवत्ता के मॉडल विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य निधि से ₹303.64 करोड़।
- पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए ₹161.13 करोड़ (राज्यांश ₹79.57 करोड़ सहित)।
- ग्रामीण छात्राओं को साईकिल वितरण के लिए राज्य निधि से ₹165.00 करोड़।
- प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य निधि से ₹150.00 करोड़।
- पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिए राज्य निधि से ₹90.00 करोड़।



महाविद्यालय शिक्षा विभाग के लिए ₹1,712.74 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए ₹225.00 करोड़ (राज्यांश ₹90.00 करोड़ सहित)।
- स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लिए राज्य निधि से ₹200.00 करोड़।
- महाविद्यालय भवनों के लिए राज्य निधि से ₹300.50 करोड़।



संस्कृत शिक्षा के लिए राज्य निधि से ₹318.86 करोड़ का प्रावधान, जिसमें संस्कृत विद्यालयों के लिए ₹270.15 करोड़ सम्मिलित है।

तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए ₹129.29 करोड़ का प्रावधान।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 9.90 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- पी.एम.पोषण शक्ति निर्माण (मिड-डे-मील) योजनान्तर्गत 53.71 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- प्रतिभावान बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 3.85 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि।
- स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत 64,420 छात्राओं को स्कूटी वितरण।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 3.66 लाख अनुसूचित जाति, 2.50 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 1.00 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 1.00 लाख अनुसूचित जाति एवं 0.95 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- साईकिल वितरण योजनान्तर्गत 3.90 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अन्तर्गत 1.00 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

4. सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन

समाज कल्याण



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए ₹20,497.03 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए राज्य निधि से ₹10,411.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना के लिए राज्य निधि से ₹4,184.00 करोड़।
- पालनहार योजना के लिए राज्य निधि से ₹1,200.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए राज्य निधि से ₹1,187.00 करोड़।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के लिए ₹418.90 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹256.47 करोड़, विधवा पेंशन हेतु ₹153.47 करोड़ एवं निःशक्तजन पेंशन हेतु ₹8.96 करोड़ सम्मिलित हैं।
- देवनारायण योजना के लिए राज्य निधि से ₹442.96 करोड़।
- लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए राज्य निधि से ₹390.00 करोड़।
- अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹503.00 करोड़ (राज्यांश ₹200.00 करोड़ सहित)।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹305.00 करोड़ (राज्यांश ₹76.25 करोड़ सहित)।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹150.00 करोड़ (राज्यांश ₹60.00 करोड़ सहित)।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए ₹100.10 करोड़।

श्रम एवं श्रम कल्याण



श्रम विभाग के लिए ₹960.79 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है :

- राज्य निधि से ₹900.00 करोड़ भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के लिये।
- गिग एवं अनऑर्गेनाइज्ड श्रमिक विकास कोष के लिये राज्य निधि से ₹50.00 करोड़।

विशेष योग्यजन निदेशालय



विशेष योग्यजन निदेशालय के लिए ₹155.58 करोड़ का प्रावधान।

जनजाति क्षेत्रीय विकास



जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये ₹1,255.10 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के ₹50.00 करोड़।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) प्रावधानों के अन्तर्गत ₹115.00 करोड़।
- धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए ₹80.00 करोड़।

महिला एवं बाल विकास



महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹1128.96 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- कालीबाई भील महिला सम्बल योजना के लिए राज्य निधि से ₹504.25 करोड़।
- लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य निधि से ₹320.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के लिए राज्य निधि से ₹86.00 करोड़।



बाल विकास सेवाओं हेतु ₹3,767.13 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- समेकित बाल विकास योजना के लिए ₹1,625.25 करोड़ (राज्यांश ₹1,233.79 करोड़ सहित)।
- पूरक पोषाहार के लिए ₹1,200.00 करोड़ (राज्यांश ₹601.90 करोड़ सहित)।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए ₹321.00 करोड़ (राज्यांश ₹164.40 करोड़ सहित)।
- इन्दिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के लिए राज्य निधि से ₹110.00 करोड़।
- राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के लिए ₹127.44 करोड़ (राज्यांश ₹51.31 करोड़ सहित)।

अल्पसंख्यक विकास



अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ₹184.10 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, जयपुर के लिए राज्यनिधि से ₹62.25 करोड़।
- प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के लिए ₹55.00 करोड़ (राज्यांश ₹22.00 करोड़ सहित)।

बाल अधिकारिता निदेशालय



बाल अधिकारिता निदेशालय के लिए ₹145.73 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए ₹100.00 करोड़ (राज्यांश ₹44.00 करोड़ सहित)।



खेल एवं युवा कल्याण के लिए राज्य निधि से ₹226.30 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- जिला खेल काम्प्लेक्स के लिए राज्य निधि से ₹120.00 करोड़।

सैनिक कल्याण



सैनिक कल्याण के लिये ₹25.84 करोड़ का प्रावधान।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

समाज कल्याण

- वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजनों के लिये मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 90.00 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.63 लाख व्यक्ति शामिल हैं:-
 - 60.25 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन।
 - 23.52 लाख विधवाओं को विधवा पेंशन।
 - 6.23 लाख व्यक्तियों को विशेष योग्यजन पेंशन।
- कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 1.97 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 4.50 लाख विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने का लक्ष्य-
 - 2.50 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।
 - 1.50 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।
 - 0.50 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- 2,000 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता अनुदान।
- 400 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान।
- विवाह हेतु 200 विशेष योग्यजनों को सहायता।
- 150 विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

- 30,375 विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावास, 97,470 विद्यार्थियों को माँ-बाड़ी केन्द्रों एवं 6,220 विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालय/मॉडल पब्लिक विद्यालय से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- 1.30 लाख सहरिया, खैरवा व कथौड़ी व्यक्तियों को दाल, तेल एवं देशी घी का मुफ्त वितरण।

महिला एवं बाल विकास

- 38 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- 4.34 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनान्तर्गत (पी.एम.एम.वी.वाई) लाभान्वित करने का लक्ष्य
- मुख्यमंत्री नारीशक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 1,200 महिलाओं को अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना।
- कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजनान्तर्गत 55,000 विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी बालिकाओं/औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।

अल्पसंख्यक विकास

- 2,998 आवेदकों को मुख्यमंत्री अनुप्रति योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

5. औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि



पेट्रोलियम निदेशालय के लिए ₹2,088.97 करोड़ का प्रावधान जिसमें HPCL राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड के लिए राज्य निधि से ₹2,088.68 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है।

उद्योग विभाग के लिए ₹2,423.95 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के लिए राज्यनिधि से ₹280.20 करोड़।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लिये राज्य निधि से ₹663.00 करोड़ एवं निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए राज्य निधि से ₹296.43 करोड़।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य निधि से ₹300.00 करोड़।



खान एवं भू-विज्ञान विभाग के लिए राज्य निधि से ₹48.02 करोड़ का प्रावधान।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए राज्य निधि से ₹45.50 करोड़ का प्रावधान।

रोजगार विभाग के लिए ₹ 1,130.92 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के लिए ₹ 825.64 करोड़।
- राजस्थान कौशल मिशन के लिए ₹ 250.00 करोड़।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यमिता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 2,500 व्यक्तियों को लाभान्वित करना।
- 1300 वर्ग किमी. में रीजनल मिनरल सर्वे करवाया जाना।
- मुख्यमंत्री युवासंबल योजना के तहत 2 लाख स्नातक बेरोजगार युवाओं को सहायता।
- रोजगार मेला के तहत 175 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन करना।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

6. पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास



पर्यटन विभाग के लिए राज्य निधि से ₹255.29 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- पर्यटन, सूचना और प्रचार के लिए ₹120.00 करोड़।

राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के लिए ₹7.19 करोड़ का प्रावधान।

देवस्थान विभाग



देवस्थान विभाग के लिए ₹160.77 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित है:

- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए ₹150.00 करोड़।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

7. आधारभूत अवसंरचना

ऊर्जा



ऊर्जा क्षेत्र के लिये ₹41,941.50 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित है:

- विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान योजना के लिए राज्य निधि से ₹29,432.39 करोड़।
- विद्युत वितरण निगमों को टेरिफ अनुदान के लिए राज्य निधि से ₹10,789.12 करोड़।



विद्युत कम्पनियों को ₹497.15 करोड़ का इक्विटी अंशदान जिसमें सम्मिलित है:

- विद्युत वितरण निगमों के लिए राज्य निधि से ₹300.00 करोड़।
- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के लिए राज्य निधि से ₹97.15 करोड़।
- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लिए राज्य निधि से ₹100.00 करोड़ का प्रावधान।



कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में राहत हेतु राज्य निधि से ₹149.97 करोड़।

विद्युत वितरण में राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान ₹708.36 करोड़।

सार्वजनिक निर्माण



सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए ₹15,078.05 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए राज्य निधि से ₹ 5,000.00 करोड़।
- राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य निधि से ₹1,650.00 करोड़।
- आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित सड़क कार्यों के लिए राज्य निधि से ₹708.00 करोड़।
- राज्य राजमार्गों के लिए राज्य निधि से ₹500.00 करोड़।
- मुख्य जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण के लिए राज्य निधि से ₹500.00 करोड़।
- बाह्य सहायतित राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना के लिए राज्य निधि से ₹687.73 करोड़ (फेज-I ₹477.45 करोड़, फेज-II ₹210.28 करोड़)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए ₹1,302.00 करोड़ (राज्यांश ₹556.80 करोड़ सहित)।
- अटल प्रगति पथ के लिए राज्य निधि से ₹400.00 करोड़।
- केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत निधि के तहत ₹1,200.00 करोड़।
- सीमा सड़कों के लिए ₹621.64 करोड़।
- राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण प्रोग्राम के लिए ₹582.00 करोड़।

परिवहन



परिवहन विभाग के लिये राशि ₹1,319.43 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण के लिये राज्य निधि से ₹550.00 करोड़।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये राज्य निधि से ₹500.00 करोड़ का अनुदान (वीजीएफ सहित)।
- पर्यावरण एवं प्रदूषण प्रबंधन के लिये राज्य निधि से ₹150.00 करोड़।
- सड़क सुरक्षा निधि के लिये राज्य निधि से ₹100.00 करोड़।



नागरिक उड्डयन विभाग के लिये राशि ₹ 121.00 करोड़ का प्रावधान।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- 190 सब स्टेशन (33/11 केवी) का निर्माण।
- 1,960 किमी (33 केवी) लाईन का निर्माण।
- 5.49 लाख नये विद्युत कनेक्शन।
- 1,30,830 सामान्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य एवं नये कृषि कनेक्शन।
- 1918.60 सर्किट किमी. (220 केवी) लाईन का निर्माण।
- 30 सब स्टेशन (220 केवी) का निर्माण।
- 2127.77 सर्किट किमी. (132 केवी) लाईन का निर्माण।
- 28 सब स्टेशन (132 केवी) का निर्माण।
- 1,715 कि.मी. राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण।
- 9,235 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण, उन्नयन एवं नवीनीकरण।
- 150 अटल प्रगतिपथों का 200 किमी में निर्माण कार्य पूर्ण करना।
- 210 कि.मी. शहरी सड़कों का सुदृढीकरण, उन्नयन एवं नवीनीकरण।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत (पीएमजीएसवाई) 2,500 कि.मी. सड़कों का निर्माण कर 1,000 गांवों/बसावटों को सड़कों से जोड़ना।
- 11 ROB एवं 05 RUB निर्माण कार्य पूर्ण करना।
- 9 उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य पूर्ण करना।
- आरएसआरटीसी बसों (राजस्थान क्षेत्र में) में मुफ्त/रियायती यात्रा के अन्तर्गत 14.00 करोड़ व्यक्तियों/यात्रियों को लाभ।
- ई-व्हीकल प्रमोशन फण्ड योजनान्तर्गत 1,59,700 व्हीकलों को अनुदान।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

8. जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

पेयजल



शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹9,409.01 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है

- शहरी जलपूर्ति योजना का पुनर्गठन/विस्तार के लिए राज्य निधि से ₹970.80 करोड़।
- वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत (एफ.एच.टी.सी.) उपलब्ध करवाये जाने के लिये राज्य निधि से ₹1654.71 करोड़।
- अनुसूचित जाति बस्तियों में जल आपूर्ति के लिए राज्य निधि से ₹448.78 करोड़।
- ईसरदा दौसा परियोजना (शहरी) के लिए राज्य निधि से ₹156.75 करोड़।
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए राज्य निधि से ₹150.00 करोड़।
- जल-जीवन मिशन अन्तर्गत संवर्द्धन एवं पुनर्गठन के लिए राज्य निधि से ₹572.00 करोड़।
- राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना के द्वितीय चरण के लिए ₹ 400.00 करोड़।



सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ₹7,808.32 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- परवन परियोजना के लिये ₹544.12 करोड़ (राज्यांश ₹408.09 करोड़ सहित)।
- सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना के लिये राज्य निधि से ₹559.62 करोड़ का प्रावधान।
- अपर हाई लेवल कैनाल ऑन माही डेम के लिये ₹650.00 करोड़ एवं नांगलिया पिकअप वेयर के लिये राज्य निधि से ₹510.00 करोड़।
- राजस्थान वाटर सेक्टर रि-स्ट्रेक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया के लिये राज्य निधि से ₹250.00 करोड़।
- जल संग्रहण संरचना कार्यों के लिये राज्य निधि से ₹327.15 करोड़।
- सिंचित क्षेत्र विकास के लिये ₹774.14 करोड़ का प्रावधान (राज्य निधि से ₹705.16 करोड़ सम्मिलित)।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के लिये राज्य निधि से ₹1,251.51 करोड़ का प्रावधान।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के लिये राज्य निधि से ₹258.67 करोड़ का प्रावधान।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 15.31 लाख फंक्शनल घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.)।
- 74,040.31 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन, जिसके अन्तर्गत-
 - 46,894 हैक्टेयर में वृहद्ध सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - 8,979 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा।
 - 18,167.31 हैक्टेयर में लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा
- 1,10,696 हैक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

9. पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता



वन विभाग के लिए ₹1,213.40 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- परिश्रंशित वनों का पुनरारोपण के लिये राज्य निधि से ₹231.35 करोड़।
- राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आरएफबीडीपी) के लिये राज्य निधि से ₹241.72 करोड़।
- जलवायु परिवर्तन एवं रेगिस्तान विस्तार की रोकथाम योजना के लिये राज्य निधि से ₹202.00 करोड़।
- राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी की तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिये राज्य निधि से ₹160.00 करोड़।



आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के लिए ₹3,317.00 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- राज्य आपदा मोचन निधि के लिए ₹1,778.00 करोड़ (राज्यांश ₹444.50 करोड़ सहित)
- प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के लिए राज्य निधि से ₹1,095.00 करोड़।
- राज्य आपदा मिटिगेशन निधि के लिए ₹444.00 करोड़ (राज्यांश ₹111.00 करोड़ सहित)



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- 71,542 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण (वानिकी) का कार्य।
- फार्म वानिकी अन्तर्गत 605.00 लाख पौध वितरण का कार्य।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

10. ग्रामीण विकास



ग्रामीण विकास क्षेत्र हेतु राशि ₹33,418.86 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को राज्य निधि से अनुदान के रूप में ₹7,000.00 करोड़।
- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के लिए ₹6,750.00 करोड़ (राज्यांश ₹2,753.12 करोड़ सहित)।
- केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में ₹5,585.50 करोड़।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹5,472.00 करोड़ (राज्यांश ₹2,188.80 करोड़ सहित)।
- केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान से संचालित योजनाओं के लिए ₹1,445.00 करोड़।
- खण्ड एवं मध्यम स्तरीय पंचायतों को सहायता के लिए राज्य निधि से ₹1410.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए राज्य निधि से ₹600.00 करोड़।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए राज्य निधि से ₹1,000.00 करोड़।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹679.00 करोड़ (राज्यांश ₹271.60 करोड़ सहित)।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल ग्रहण घटक) के लिए ₹518.00 करोड़ (राज्यांश ₹207.20 करोड़ सहित)।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹385.00 करोड़ (राज्यांश ₹154.00 करोड़ सहित)।
- जिला परिषदों को सहायता के लिए राज्य निधि से ₹261.00 करोड़।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के लिए ₹300.00 करोड़।
- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) के लिए राज्य निधि से ₹100.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए ₹61.00 करोड़।
- मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹50.00 करोड़।
- मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹50.00 करोड़।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत 80,000 व्यक्तिगत शौचालय और 4,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अन्तर्गत 1.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित करना (वॉटरशेड कम्पोनेन्ट)।
- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 5.85 करोड़ थालियां उपलब्ध कराना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 3 लाख आवासों का निर्माण।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

11. शहरी विकास



आवास एवं नगरीय विकास क्षेत्र के लिये ₹20,323.61 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- चुंगी समाप्ति पुनर्भरण के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए राज्य निधि से ₹3,860.12 करोड़।
- केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹1,629.01 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को राज्य निधि से अनुदान के रूप में ₹2,286.02 करोड़।
- अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन (अमृत) मिशन-2.0 के लिए ₹6,765.66 करोड़ (राज्यांश ₹4,528.11 करोड़ सहित)।
- राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के लिए राज्य निधि से ₹812.66 करोड़।
- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के लिए राज्य निधि से ₹1,414.48 करोड़।
- स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की मरम्मत/ पुनरुद्धार के लिए राज्य निधि से ₹500.00 करोड़।
- स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के लिए ₹1,289.25 करोड़ (राज्यांश ₹660.58 करोड़ सहित)।
- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए राज्य निधि से ₹200.00 करोड़।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ₹684.11 करोड़ का प्रावधान जिसमें राज्य निधि से ₹273.64 करोड़ सम्मिलित हैं।



महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:

- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी) अन्तर्गत 9.75 करोड़ थालियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (एमएसआरजीवाई) अन्तर्गत 2.36 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।
- 29,461 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का (स्वच्छ भारत मिशन-2.0) निर्माण।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत 50,000 आवासों का निर्माण।
- अमृत 2.0 के अन्तर्गत 3,486.79 किमी सीवर लाईन बिछाना, 212.35 एमएलडी के 31 नये एसटीपी का निर्माण।
- 4.27 लाख घरेलू सीवर कनेक्शन उपलब्ध करवाना।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

12. प्रभावी प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवाएं



सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए ₹1,467.79 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- राजीव गाँधी फिनटेक डिजीटल इंस्टीट्यूट जोधपुर के लिए राज्य निधि से ₹101.50 करोड़।
- कमान्ड एवं कंट्रोल सेन्टर के लिए राज्य निधि से ₹150.00 करोड़।
- राजनेट के लिए राज्य निधि से ₹289.00 करोड़।



आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए ₹371.22 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित हैं:

- पंच गौरव कार्यक्रम के लिए राज्य निधि से ₹91.18 करोड़।



विधि विभाग के लिए ₹519.94 करोड़ का प्रावधान जिसमें राज्य निधि से ₹325.84 करोड़ सम्मिलित।

पुलिस विभाग के लिए ₹556.16 करोड़ का प्रावधान।

होम गार्ड्स विभाग के लिए ₹139.38 करोड़ का प्रावधान।

सामान्य प्रशासन विभाग के लिए राज्य निधि से ₹328.48 करोड़ का प्रावधान।

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं

13. वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति



वाणिज्य कर विभाग के लिए राज्य निधि से ₹214.08 करोड़ का प्रावधान जिसमें सम्मिलित है:

- राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति के तहत अनुदान के लिए राज्य निधि से ₹177.25 करोड़ का प्रावधान ।



राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए ₹12.37 करोड़ का प्रावधान ।

कोष एवं लेखा विभाग के लिए राज्य निधि से ₹138.42 करोड़ का प्रावधान।

BUDGET AT A GLANCE

INTRODUCTION

Budget at a Glance presents broad aggregate of the Budget for easy understanding. This document shows receipts and expenditure as well as the Fiscal Deficit (FD), Revenue Deficit (RD) and the Primary Deficit (PD) of the Government of Rajasthan. It gives an illustrative account of sources of receipts and expenditure through graphs and info-graphics.

IMPORTANT DEFINITIONS

Revenue Receipts: Revenue receipts include State's own tax revenue, share in central taxes, State's non-tax revenue and central assistance.

State's Own Tax Revenue: Tax revenue collected by State as per notification issued under any Act established by law.

Share in Central Taxes: According to article 280 of constitution, amount transferred by union government to States as per recommendation of finance commission is termed as share in central taxes.

Non-tax Revenue: Revenue received from user charges, fees, royalties, penalties, interest receipts etc., for services provided by State government departments is classified as non-tax revenue.

Central Assistance: Receipts from central government as per recommendation of finance commission, central share in centrally sponsored scheme and miscellaneous receipts in the form of revenue are termed as central assistance.

Revenue Expenditure: Charges for maintenance, repair, upkeep and working expenses, which are required to maintain the assets in a running order as also all other expenses incurred for the day to day running of the office, including establishment and administrative expenses are termed as revenue expenditure.

Capital Outlay: An expenditure incurred to create future benefits like acquisition of tangible assets of material and permanent nature such as land, building, machines, upgradation of existing facilities or assets to add values to the same and includes investment in shares by the government.

Revenue Deficit: It is the excess of revenue expenditure over revenue receipts of the government in a given financial year. A negative figure for revenue deficit would represent revenue surplus.

Fiscal Deficit: Fiscal Deficit is the difference between total expenditure and the Revenue Receipts (including Non-Debt Capital Receipts). Fiscal Deficit is reflective of the total borrowing requirement of Government.

Primary Deficit: It is the deficit obtained by subtracting interest payments from the fiscal deficit of the State in a given financial year. Primary deficit corresponds to the net borrowing required to meet expenditure excluding the interest payments. A negative figure for primary deficit would represent primary surplus.

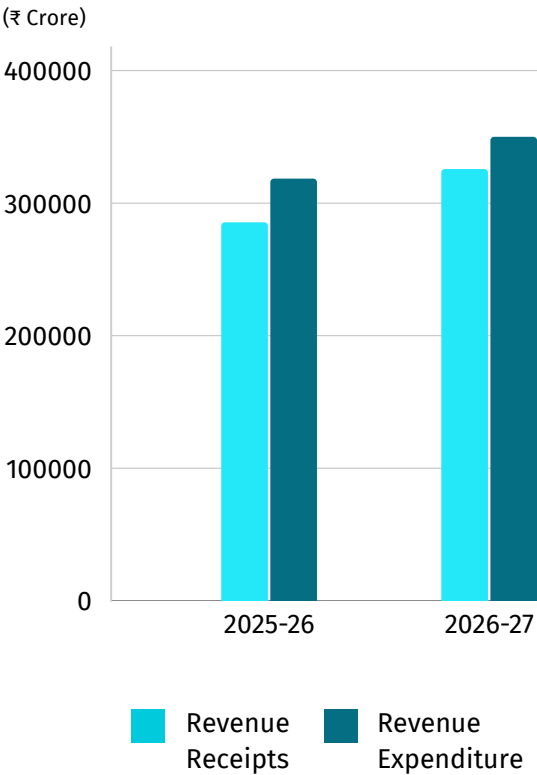
BUDGET AT A GLANCE

(₹ in Lakh)

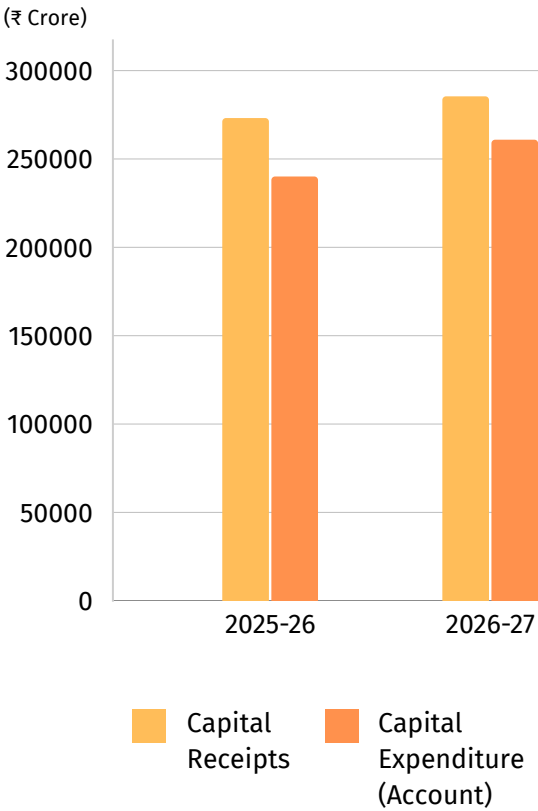
S.N.	PARTICULARS	R.E. 2025-26	B.E. 2026-27
1	Total Receipts	55868198.66	61117400.07
1A	Revenue Receipts	28553334.34	32574013.55
1B	Capital Receipts	27314864.32	28543386.52
1B(i)	Of Which Non Debt Receipts	144618.20	39980.98
2	Total Expenditure	55859615.59	61095630.01
2A	Revenue Expenditure	31851625.73	35005407.08
2A(i)	Of Which Interest Payment	4296067.76	4367521.93
2B	Capital Expenditure (Account)	24007989.86	26090222.93
2B(i)	Of which Capital Outlay	3942917.44	5397841.08
2B(ii)	Loans & Advances	152671.37	159998.78
3	Revenue Deficit (2A-1A)	3298291.39	2431393.53
4	Budgetary Surplus (1-2)	8583.07	21770.06
5	Fiscal Deficit [(2A+2B(i)+2B(ii))-(1A+1B(i))]	7249262.00	7949252.41
6	Primary Deficit [5-2A(i)]	2953194.24	3581730.48

BUDGET AT A GLANCE

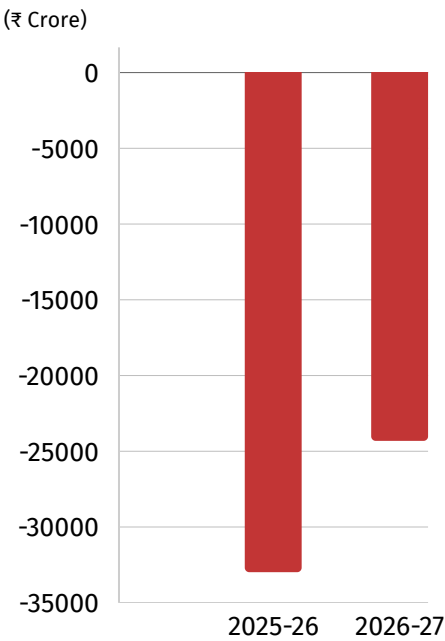
REVENUE



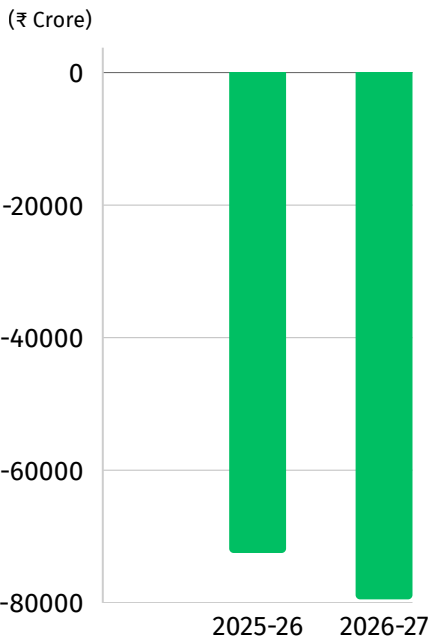
CAPITAL



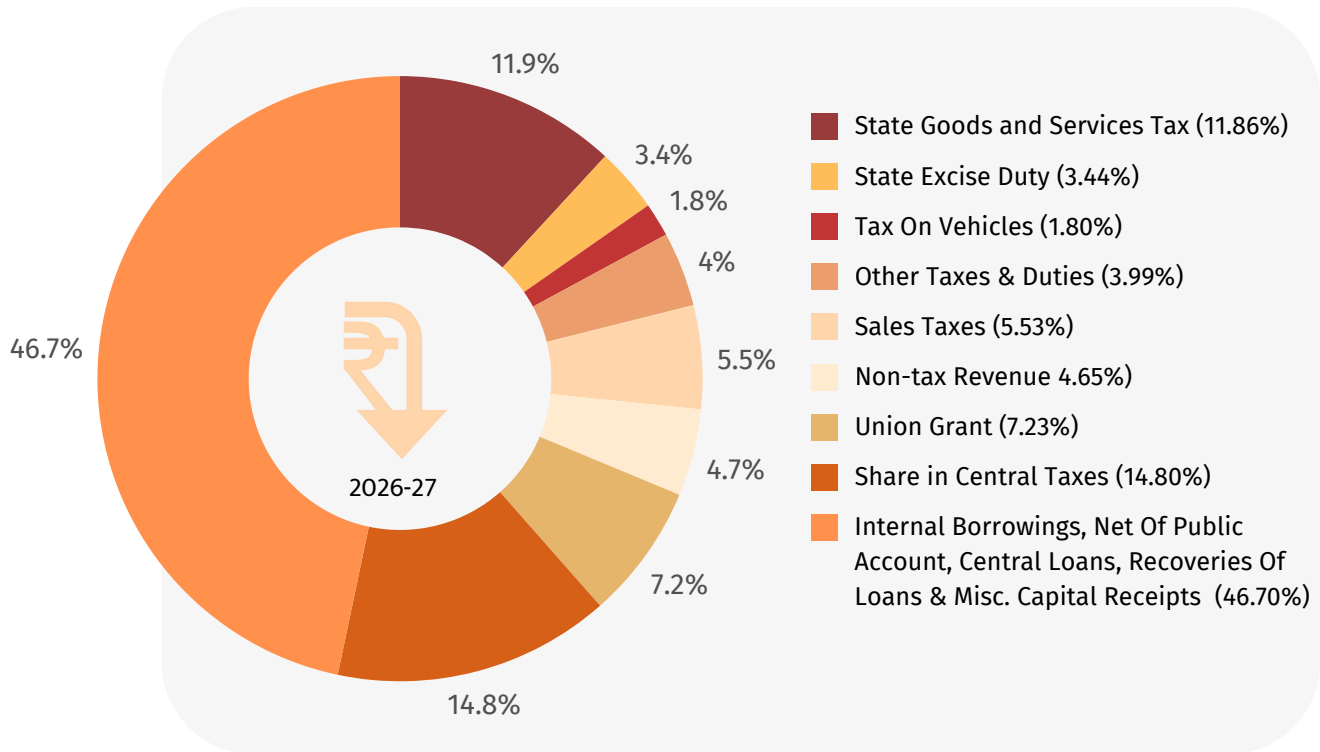
REVENUE DEFICIT (-)



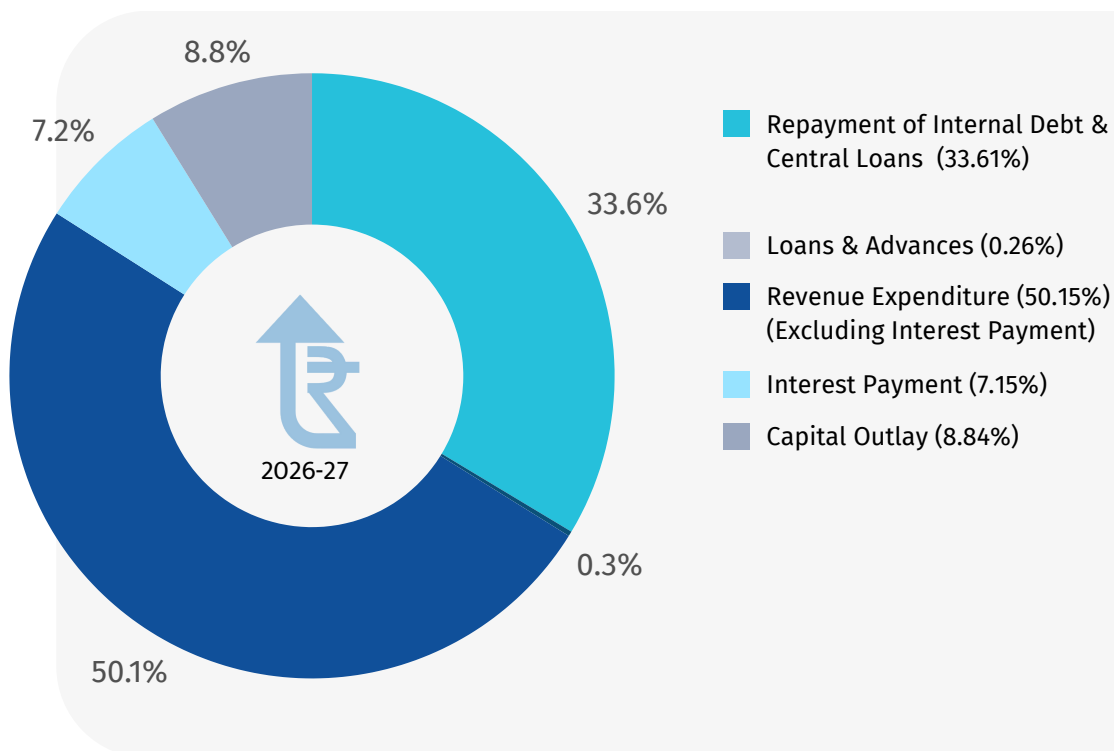
FISCAL DEFICIT (-)



RUPEE COMES FROM



RUPEE GOES TO



RECEIPTS

(₹ in Lakh)

S.N.	PARTICULARS	R.E. 2025-26	B.E. 2026-27
1	Own Tax Revenue	13853935.91	16266847.42
i	State Goods and Services Tax	6170000.00	7250000.00
ii	Land Revenue	176130.50	178145.52
iii	Stamps & Registration	1500000.00	1875000.00
iv	State Excise Duty	1900000.00	2100000.00
v	Sales Tax	2800000.00	3380000.00
vi	Tax on Vehicles	960000.00	1100000.00
vii	Taxes & Duties on Electricity	342500.00	378500.00
viii	Other Taxes & Duties	5305.41	5201.90
2	Share in Central Taxes	8394045.00	9044585.00
i	Goods and Services Tax	2363483.00	2473689.00
ii	Income Tax	2969533.00	3218725.00
iii	Corporation Tax	2477818.00	2655056.00
iv	Union Excise Duty	124913.00	205569.00
v	Custom Duty	451333.00	482556.00

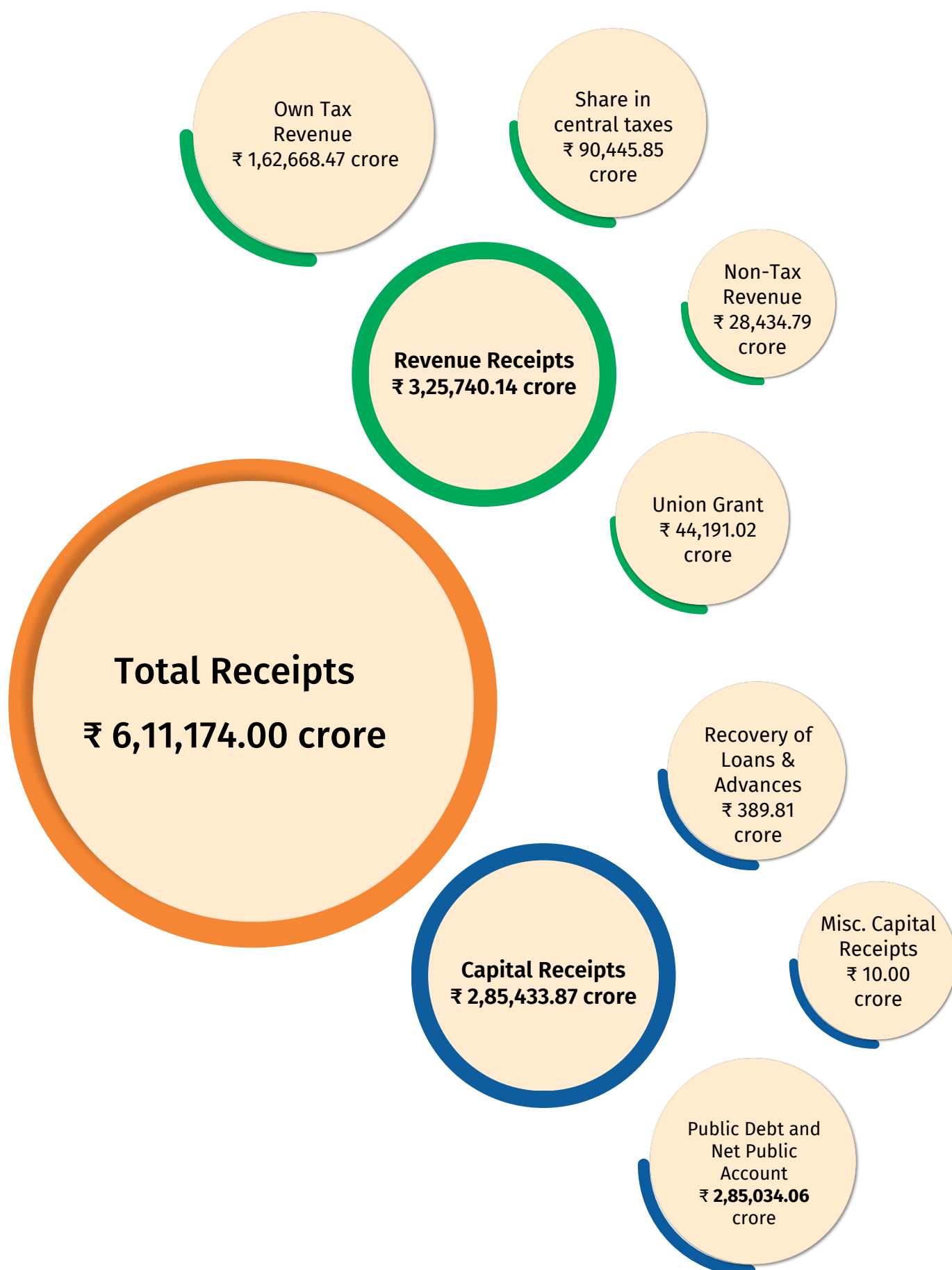
RECEIPTS

(₹ in Lakh)

S.N.	PARTICULARS	R.E. 2025-26	B.E. 2026-27
vi	Service Tax	-293	0
vii	Other Taxes	7258	8990
3	Non Tax Revenue	2514307.76	2843479.26
i	Mines	1178000	1372500
ii	Petroleum	210000	230000
iii	Interest Receipts	269711.69	309735.26
iv	Other Non-Tax Revenue	856596.07	931244
4	Union Grant	3791045.67	4419101.87
5	Total Revenue Receipts (1+2+3+4)	28553334.34	32574013.55
6	Capital Receipts	27314864.32	28543386.52
i	Recovery of Loans and Advances	143618.2	38980.98
ii	Internal Debt	25050587.82	25768896.04
iii	Loans from Central Government	1203653.01	1765144.01
iv	Net Public Account	916005.29	969365.49
v	Misc. Capital Receipts	1000	1000
7	Total Receipts (5+6)	55868198.66	61117400.07

RECEIPTS

2026-27



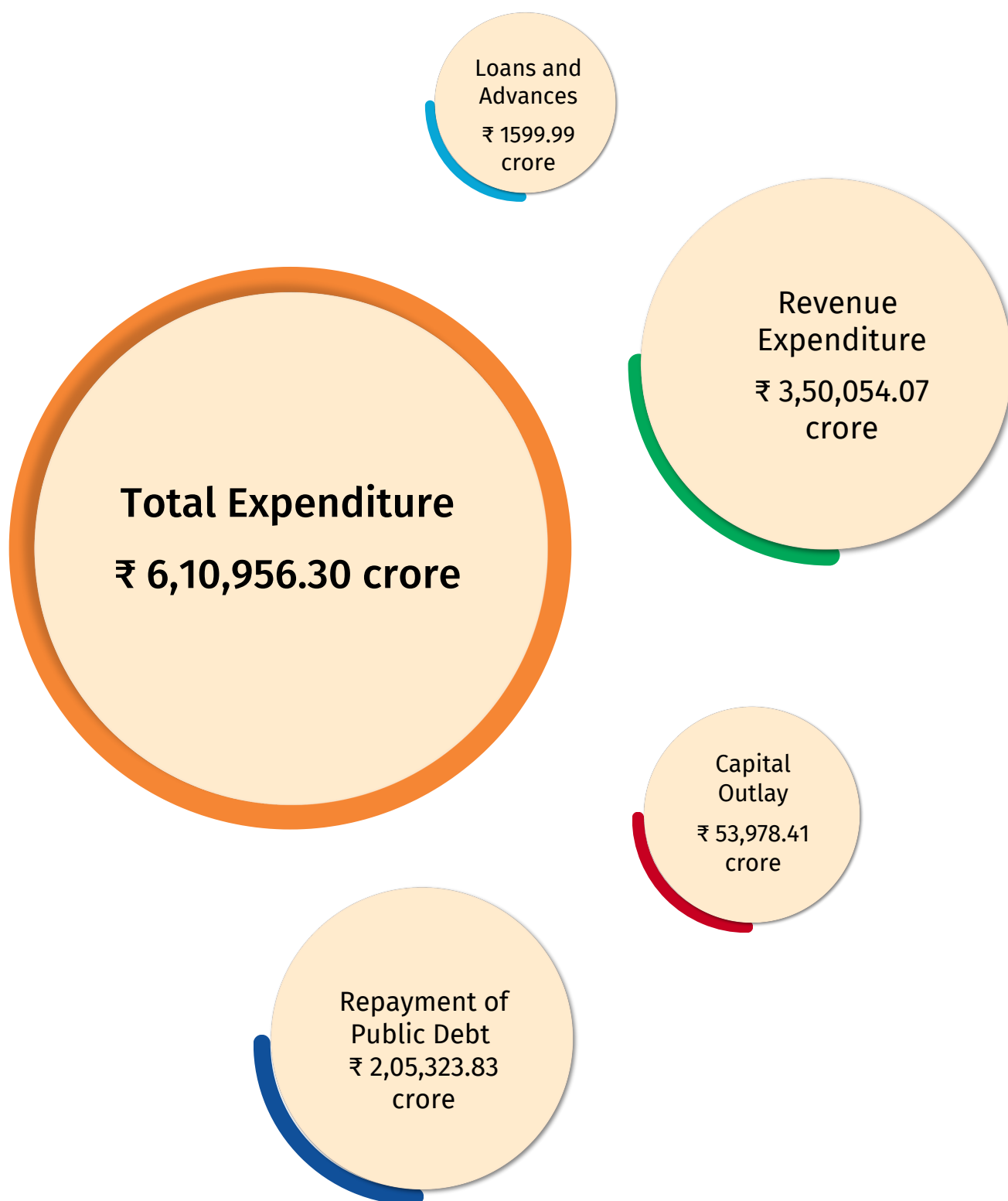
EXPENDITURE

(₹ in Lakh)

S.N.	PARTICULARS	R.E. 2025-26	B.E. 2026-27
I	Revenue Expenditure	31851625.73	35005407.08
i	General Services	9911143.43	10426903.14
ii	Social Services	13379069.71	14331432.77
iii	Economic Services	8561408.14	10247071.16
iv	Grants-in-aid & Contributions	4.45	0.01
II	Capital Expenditure	24007989.86	26090222.93
1	Capital Outlay	3942917.44	5397841.08
i	General Services	91326.78	149182.54
ii	Social Services	1617646.76	2689219.73
iii	Economic Services	2233943.90	2559438.81
2	Repayment of Public Debt	19912401.05	20532383.07
3	Loan and Advances	152671.37	159998.78
	Total Expenditure	55859615.59	61095630.01

EXPENDITURE

2026-27





AGRICULTURE BUDGET

TOTAL EXPENDITURE ON AGRICULTURE, FARMER WELFARE AND ALLIED ACTIVITIES

(₹ in Lakh)

S.N.	SECTOR	B.E. 2026-27
1	Agriculture Subsidy (Power subsidy, Interest subsidy and Grant to Gaushala etc.)	4219110.74
2	Agriculture Credit (Short term agriculture loan to farmers)	2548000.02
3	Dams, Canals, agriculture connection and Other Infrastructure Development	1813207.06
4	Agriculture Insurance (Crop and cattle insurance etc)	598793.19
5	Social Security (MNERGA, Pension to small And marginal farmers etc.)	703982.91
6	Agriculture Produce Marketing Committee	900170.51
7	Agriculture Governance	491501.34
8	Other Activities related to Agriculture	484707.28
9	Agriculture Education, Research and Skill Development	181338.44
	Total	11940811.48



SCHEDULED TRIBE SUB PLAN BUDGET

SCHEMETIC OUTLAY UNDER SCHEDULED TRIBE SUB PLAN

(₹ in Lakh)

S.N.	SECTOR	B.E. 2026-27
1	Transforming Agri-food Systems	222742.20
2	Health and Well-being	375686.33
3	Education and the Knowledge Economy	550058.38
4	Social Empowerment and Inclusion	472727.15
5	Industrial, Mining and Economic Growth	88008.93
6	Tourism and Cultural Development	4468.72
7	Core Infrastructure	766066.17
8	Water Security and Resilience	293920.69
9	Environmental Sustainability and Climate Resilience	29782.49
10	Rural Development	509259.93
11	Urban Development	252792.29
12	Effective Governance and Public Services	32666.31
13	Fiscal Management and Economic Policy	20193.67
	Total	3618373.26



SCHEDULED CASTE SUB PLAN BUDGET

SCHEMETIC OUTLAY UNDER SCHEDULED CASTE SUB PLAN

(₹ in Lakh)

S.N.	SECTOR	B.E. 2026-27
1	Transforming Agri-food Systems	285077.27
2	Health and Well-being	525378.99
3	Education and the Knowledge Economy	682541.28
4	Social Empowerment and Inclusion	525806.92
5	Industrial, Mining and Economic Growth	100562.50
6	Tourism and Cultural Development	4785.11
7	Core Infrastructure	1238006.40
8	Water Security and Resilience	246535.30
9	Environmental Sustainability and Climate Resilience	46535.71
10	Rural Development	593542.11
11	Urban Development	348420.42
12	Effective Governance and Public Services	37167.22
13	Fiscal Management and Economic Policy	65260.01
	Total	4699619.24



GENDER BUDGET

SCHEMETIC OUTLAY FOR WOMEN AND GIRLS

(₹ in Lakh)

S.N.	SECTOR	B.E. 2026-27 (Category 'A' - Details of Specific Sectors with 70 Percent and Above Provision)	B.E. 2026-27 (Category 'B' - Details of specific sectors with less than 70 percent provisions)
1	Transforming Agri-food Systems	6425.00	144365.49
2	Health and Well-being	162018.93	1053368.12
3	Education and the Knowledge Economy	204253.94	1688490.82
4	Social Empowerment and Inclusion	759260.57	852715.91
5	Industrial, Mining and Economic Growth	-	61589.47
6	Tourism and Cultural Development	-	7957.50
7	Core Infrastructure	-	1665025.43
8	Water Security and Resilience	-	17573.95
9	Environmental Sustainability and Climate Resilience	-	114.01
10	Rural Development	93582.53	632626.11
11	Urban Development	-	39820.51
12	Effective Governance and Public Services	6412.96	35621.54
	Total	1231953.93	6199268.88



CHILD BUDGET

SCHEMETIC OUTLAY FOR EDUCATION, HEALTH, PROTECTION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN UNDER 18 YEARS

(₹ in Lakh)

S.N.	SECTOR	B.E. 2026-27
1	Health and Well-being	8616.13
2	Education and the Knowledge Economy	4326667.71
3	Social Empowerment and Inclusion	778498.43
	TOTAL	5113782.27



GREEN BUDGET

SCHEMATIC OUTLAY FOR ENVIRONMENT PROTECTION AND GREEN GROWTH

(₹ in Lakh)

S.N.	SECTOR	B.E. 2026-27
1	Transforming Agri-food Systems	530564.39
2	Health and Well-being	20527.01
3	Education and the Knowledge Economy	20807.18
4	Social Empowerment and Inclusion	6318.30
5	Industrial, Mining and Economic Growth	4270.05
6	Tourism and Cultural Development	188.54
7	Core Infrastructure	854575.31
8	Water Security and Resilience	776346.81
9	Environmental Sustainability and Climate Resilience	189716.65
10	Rural Development	683437.79
11	Urban Development	163566.00
12	Effective Governance and Public Services	97227.74
13	Fiscal Management and Economic Policy	7.06
	Total	3347552.83

HIGHLIGHTS OF SCHEMATIC OUTLAY (2026 - 27)

2,62,781.58
Crore



Transforming Agri-Food System

14398.20 Crore

5.48%



Health and Well-being

27069.37 Crore

10.3%



Education and the Knowledge
Economy

46017.40 Crore

17.51 %



Social Empowerment and
Inclusion

28489.35 Crore

10.84 %



Industrial, Mining and Economic
Growth

6441.07 Crore

2.45 %



Tourism and Cultural Development

509.92 Crore

0.19 %



Core Infrastructure

58460.44 Crore

22.25 %



Water Security and Resilience

17220.30 Crore

6.55 %



Environmental Sustainability and
Climate Resilience

4536.64 Crore

1.73 %



Rural Development

33418.86 Crore

12.72 %



Urban Development

20323.61 Crore

7.73 %



Effective Governance and Public
Services

3799.98 Crore

1.45 %



Fiscal Management and
Economic Policy

2096.44 Crore

0.8 %

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

1. TRANSFORMING AGRI-FOOD SYSTEMS:



Provision of ₹4,147.51 crore for Agriculture Department which includes:

- ₹2,298.71 crore for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana & Weather Based Crop Insurance Scheme from State fund.
- ₹252.14 crore (including State share of ₹98.65 crore) for National Food Security Mission.
- ₹200.00 crore (including State share of ₹79.99 crore) for National Mission on Agriculture Extension and Technology.
- ₹210.00 crore (including State share of ₹84.00 crore) for Rastriya Krishi Vikas Yojana.
- ₹80.06 crore (including State share of ₹32.02 crore) for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.
- ₹72.23 crore (including State share of ₹28.89 crore) for National Mission on Natural Farming.
- ₹61.70 crore (including State share of ₹24.68 crore) for National Mission on Sustainable Agriculture.
- ₹59.59 crore (including State share of ₹25.14 crore) for Paramparagat Krishi Vikas Yojana.
- ₹274.19 crore (including State share of ₹104.47 crore) for Mission for Atma-Nirbharta in Pulses.



Provision of ₹1,596.71 crore for Horticulture Department which includes:

- ₹600.00 crore (including State share of ₹240.00 crore) for Micro Irrigation Scheme.
- ₹400.13 crore from State fund for PM KUSUM Scheme (Component-B).
- Additional Subsidy of ₹300.00 crore from State fund for Micro Irrigation Scheme.
- ₹149.90 crore (including State share of ₹59.96 crore) for National Horticulture Mission



Provision of ₹390.08 crore for Five Agriculture Universities.



Provision of ₹750.76 crore for Agriculture Marketing which includes;

- ₹350.00 Crore from State fund for Development Schemes of Rajasthan State Agriculture Marketing Board.
- ₹45.96 crore (including State share of ₹18.38 crore) for PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme.



Provision of ₹1,308.62 crore for Animal Husbandry Department which includes:

- ₹674.94 crore from State fund for Veterinary Hospitals and Dispensaries
- ₹100.00 crore from State fund for Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana
- ₹103.48 crore from State fund for Mukhymantri Pashudhan Nishulk Dava Yojana



Provision of ₹91.33 crore for Veterinary & Animal Science University, Bikaner.



Provision of ₹2,609.18 crore for Gopalan Department which includes:

- ₹1,400.00 crore for grant to Goshalas from State fund.
- ₹700.00 crore for Mukhyamantri Milk Producer Sambal Scheme from State fund.
- ₹27.00 crore for Nandishala Scheme from State fund.



Provision of ₹3,374.50 crore for Cooperative Department, which includes:

- ₹1,973.83 crore from State fund for Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana.
- ₹700.00 crore from State fund for Interest subsidy to good loanee of cooperative societies.
- ₹465.00 crore from State fund for Interest Subsidy for Credit Cooperative Institutions.



Provision of ₹75.74 crore from State fund for Watershed Development and Soil Conservation.



Important Physical Targets:

- Area under Food Crops – 162.25 lakh hect.
- Production of Food Grains – 283.15 lakh M.T.
- Area under Oilseeds – 67.02 lakh hect.
- Production of Oilseeds – 111.05 lakh M.T.
- Area under Sugarcane – 0.05 lakh hect.
- Production of Sugarcane – 4.05 lakh M.T.
- Area under Cotton – 7.50 lakh hect.
- Production of Cotton – 28.73 lakh bales
- Artificial Insemination – 38.66 lakh
- Castration – 10.08 lakh
- Fish Production – 1,17,000 M.T.
- Installation of 50,000 solar system under PM-KUSUM (Component-B) Scheme.
- Installation of Micro irrigation system in 03 lakh hectares area under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Micro Irrigation).
- Free distribution of mini kits to 07 lakh farmers for various crops (Bajra, Moong, Jowar, Maize, Moth and Mustard seeds).
- To benefit 71.83 lakh farmers under the Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

2. HEALTH AND WELL-BEING

HEALTH



Provision of ₹12,195.81 crore for Medical & Health Department which includes:

- ₹3,000.00 crore from State fund for Mukhyamantri Ayushman Aarogya Yojana.
- ₹3,817.09 crore from State fund for Rajasthan Government Health Scheme 2021.
- ₹1,548.92 crore from State fund for Mukhyamantri Nisulk Nirogi Rajasthan Yojana.
- ₹1,062.00 crore from State fund for Community Health Centers.
- ₹686.16 crore from State fund for Primary Health Centers.
- ₹271.93 crore from State fund for Health Sub-Centers.
- ₹250.00 crore from State fund for construction of buildings of Primary Health Centers and Community Health Centers under NABARD.



Provision of ₹4,853.56 crore for National Rural Health Mission which includes:

- ₹3,392.62 crore (including State share of ₹1,357.05 crore) for National Ayush Mission.
- ₹876.20 crore (including State share of ₹350.48 crore) for PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission.



Provision of ₹1,798.08 crore for Family Welfare Department which includes:

- ₹1,046.36 crore (including State share of ₹98.41 crore) for Rural Sub-Centers.
- ₹335.50 crore from State fund for Mother & Child Health Vaccination and Family Welfare Programme.
- ₹193.17 crore (including State share of ₹135.07 crore) for District Family Welfare Bureau.
- ₹127.60 crore (including State share of ₹83.95 crore) for Urban Family Welfare Centers.



Provision of ₹2,995.46 crore for Medical Education Department which includes:

- ₹1,541.23 crore (including State share of ₹740.43 crore) for New Medical Colleges.
- ₹1,123.50 crore from State fund for Rajasthan Medical Education Society.



Provision of ₹865.42 crore (including State share of ₹842.94 crore) for Medical College, Jaipur.

Provision of ₹461.63 crore from State fund for Medical College, Jodhpur.

Provision of ₹333.69 crore (including State share of ₹313.40 crore) for Medical College, Udaipur.

Provision of ₹341.50 crore (including State share of ₹325.34 crore) for Medical College, Kota.

Provision of ₹345.02 crore (including State share of ₹290.44 crore) for Medical College, Ajmer.

Provision of ₹276.97 crore (including State share of ₹239.44 crore) for Medical College, Bikaner.



Provision of ₹787.67 crore (including State share of ₹553.67 crore) for Ayush (Ayurved, Unani and Homeopathy).

Provision of ₹10.50 crore from State fund for Rajasthan Health Science University, Jaipur.



Provision of ₹52.24 crore for Commissionerate of Food Safety and Drug Control which includes:

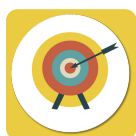
- ₹33.20 crore from State fund for Shudh ke Liye Yudh Abhiyan.

FOOD & CIVIL SUPPLY DEPARTMENT



Provision of ₹1,750.24 crore for Food & Civil Supply Department which includes:

- ₹586.02 crore (including State share of ₹348.12 crore) for National Food Security Scheme.
- ₹900.00 crore from State fund for Rasoi Gas Cylinder Subsidy Yojana.
- ₹245.00 crore from State fund for Rajasthan Krashak Samarthan Yojana.



Important physical targets:

- Health assurance coverage to 1.37 crore families under Mukhya Mantri Ayushman Arogya (MAA) Yojana.
- Construction of buildings for 05 District Hospitals, 15 Sub-District Hospitals, 03 Mother Child Hospitals, 101 Community Health Centers, 03 Urban Community Health Centers, 19 Primary Health Centers, 38 Trauma Centers, 03 Urban Primary Health Centers, 47 Sub-Health Centers and 09 Satellite Hospitals.
- Target to benefit 20 crore patients under Mukhyamantri Nishulk Nirogi Rajasthan Yojana (DAWA).
- To increase of 120 UG seats and 235 PG seats in Medical Colleges operating under RajMES.
- To increase of 50 BDS seats in RUHS Dental College.
- To organize 370 International Yoga Day programs at State, District and Block level.
- To organize 07 Arogya Mela at State and Division level.

FOOD & CIVIL SUPPLY DEPARTMENT

- To benefit 1.08 crore NFSA families under LPG Cylinder Subsidy Scheme.
- To benefit 4.47 crore people under the National Food Security Scheme.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

3. EDUCATION AND THE KNOWLEDGE ECONOMY

Provision of ₹46,017.40 crore for Education.

Education



Provision of ₹21,646.29 crore for Elementary Education which includes:

- ₹13,767.54 crore (including State share of ₹9,745.11 crore) for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA).
- ₹5,653.15 crore from State fund for Primary Schools through Panchayati Raj Department.
- ₹1,250.00 crore (including State share of ₹919.46 crore) for reimbursement of tuition fee to Private Schools under Right to Education (R.T.E.) Act.
- ₹91.61 crore (including State share of ₹37.24 crore) for Samagra Shiksha – STAR Project.
- ₹434.67 crore (including State share of ₹173.87 crore) for PM Shree Yojana
- ₹150.00 crore (including State share of ₹81.00 crore) for Free text Books distribution in Government Schools for class 1 to 8 students.



Provision of ₹2,091.80 crore for Mid Day Meal which includes ₹798.00 crore from State fund for Pannadhay Bal Gopal Yojana and ₹1,293.80 crore (including State share of ₹592.52 crore) for PM Poshan Yojana.



Provision of ₹19,473.51 crore for Secondary Education which includes:

- ₹14,842.79 crore from State fund for Secondary Schools.
- ₹2,821.63 crore (including State share of ₹1,588.36 crore) for Samagra Shiksha Abhiyan (SAMSA).
- ₹303.64 crore from State fund for establishment of High Quality Model Schools at Block Level.
- ₹161.13 crore (including State share of ₹79.57 crore) for Pre-Matric Scholarship to SC/ST/OBC.
- ₹165.00 crore from State fund for Cycle Distribution to rural girl students.
- ₹150.00 crore from State fund for Incentive to Meritorious girl Students.
- ₹90.00 crore from state fund for Free text Book Distribution.



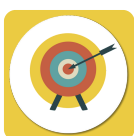
Provision of ₹1,712.74 crore for College Education Department which includes:

- ₹225.00 crore (including State share of ₹90.00 crore) for Rastriya Uchattar Shiksha Abhiyan (RUSA).
- ₹200.00 crore from state fund for Swami Vivekananda Scholarship for Academics Excellence Yojana.
- ₹300.50 crore from State fund for college buildings.



Provision of ₹318.86 crore from State fund for Sanskrit Education, which includes ₹270.15 crore for Sanskrit Schools.

Provision of ₹129.29 crore for Technical Education Department.



Important physical targets:

- Target to benefit 9.90 lakh students under Right To Education (R.T.E.)
- Target to benefit 53.71 lakh students under Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (Mid Day Meal) Yojana.
- Benefit to 3.85 lakh Girl students under Incentive for Meritorious Girl scheme.
- Benefit to 64,420 Girl students under Scooty Distribution scheme.
- Target to benefit 3.66 lakh SC Students, 2.50 lakh ST Students and 1.00 lakh OBC Students under Pre-Matric Scholarship for Secondary Education Department.
- Target to benefit 1.00 lakh SC Students and 0.95 lakh ST Students under Pre-Matric Scholarship for Elementary Education Department.
- Target to benefit 3.90 lakh Girl students under Cycle Distribution scheme.
- Target to benefit 1.00 Lakh students under CM Higher Education Scholarship.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

4. SOCIAL EMPOWERMENT AND INCLUSION

SOCIAL WELFARE



Provision of ₹20,497.03 crore for Social Justice & Empowerment Department which includes:

- ₹10,411.00 crore from State fund for Chief Minister Old Age Samman Pension Yojana.
- ₹4,184.00 crore from State fund for Chief Minister Widow Samman Pension Yojana.
- ₹1,200.00 crore from State fund for Palanhar Scheme.
- ₹1,187.00 crore from State fund for Chief Minister Specialty Abled Samman Pension Yojana.
- Provision of ₹418.90 crore for National Social Assistance Programme (NSAP) which includes ₹256.47 crore for Old Age Pension, ₹153.47 crore for Widow Pension & ₹8.96 crore for Specially Abled Pension.
- ₹442.96 crore from State fund for Devnarayan Yojana
- ₹390.00 crore from State fund for Small & Marginal Old aged Farmers Samman Pension Scheme.
- ₹503.00 crore (including State share of ₹200.00 crore) for Post-Matric Scholarship to SC Students.
- ₹305.00 crore (including State share of ₹76.25 crore) for Post-Matric Scholarship to ST Students.
- ₹150.00 crore (including State share of ₹60.00 crore) for Post-Matric Scholarship to OBC Students.
- ₹100.10 crore for PM Aadarsh Gram Yojana.

Labour & Labour Welfare



Provision of ₹960.79 crore for Labour Department which includes:

- ₹900.00 crore from State fund for Building and Other Construction Labour Welfare Board.
- ₹50.00 crore from State fund for Gig and un-organized labour development fund.

Directorate of Specially Abled Person



Provision of ₹ 155.58 crore for Directorate of Specially Abled Persons.

Tribal Area Development



Provision of ₹1,255.10 crore for Tribal Area Development which includes:

- ₹50.00 crore as Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan.
- ₹115.00 crore under proviso to Article 275(1) of the Constitution of India.
- ₹80.00 crore for Dharti Aabha Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan.

Women and Child Development



Provision of ₹1,128.96 crore for Women Development programme which includes:

- ₹504.25 crore from State fund for Kali Bai Bheel Mahila Sambal Yojana.
- ₹320.00 crore from State fund for Lado Protsahan Yojana.
- ₹86.00 crore from State fund for Mukhya Mantri Nari Shakti Training and Skill Promotion Yojana.



Provision of ₹3,767.13 crore for Child Development Services which includes:

- ₹1,625.25 crore (including State share of ₹1,233.79 crore) for ICDS.
- ₹1,200.00 crore (including State share of ₹601.90 crore) for Supplementary Nutrition.
- ₹321.00 crore (including State share of ₹164.40 crore) for PM Matru Vandana Yojana.
- ₹110.00 crore from State fund for Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana.
- ₹127.44 crore (including State share of ₹51.31 crore) for National Nutrition Mission.

Minority Development



Provision of ₹184.10 crore for Minority Welfare which includes:

- ₹62.25 crores from State fund for Model Residential School, Jaipur.
- ₹55.00 crore (including State share of ₹22.00 crore) for Pradhan Mantri Jan Vikas Programme.

Directorate of Child Empowerment



Provision of ₹145.73 crore for Directorate of Child Empowerment which includes:

- ₹100.00 crore (including State share of ₹44.00 crore) for Integrated Child Protection Scheme.



Provision of ₹226.30 crore from State fund for Sports & Youth Welfare which include:

- ₹120.00 crore from State fund for District Sport Complex.

Soldier Welfare



Provision of ₹25.84 crore for Soldiers Welfare.



Important Physical Targets:

Social Welfare

- Target to benefit 90.00 lakh persons under Chief Minister Samman Pension Yojana for old age, widow and specially abled persons. which includes 12.63 lakh persons under National Social Assistance Programme (NSAP):
 - Old-age Pension to 60.25 lakh persons.
 - Widow Pension to 23.52 lakh widows.
 - Specially Abled Pension to 6.23 lakh persons.
- Target to benefit 1.97 lakh persons under Farmers Old Age Pension Scheme.
- Target to benefit 4.50 lakh SC/ST/OBC students under Post-Matric Scholarship:
 - Scholarship to 2.50 lakh SC students.
 - Scholarship to 1.50 lakh ST students.
 - Scholarship to 0.50 lakh OBC students.

Directorate of Specially Abled Person

- Assistance for Prosthetic Aid to 2,000 persons.
- Subsidy to 400 persons under Mukhya Mantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana.
- Assistance to 200 special abled persons for marriage.
- Scholarship to 150 Specially Abled Students.

Tribal Area Development

- Target to benefit 30,375 students through Ashram Hostels, 97,470 students through Maa-Bari Centers and 6,220 Students through Residential School/Modal Public School.
- Free distribution of Pulses, Oil & Ghee to 1.30 lakh Saharia, Khairwa and Kathori persons.

Women and Child Development

- Target to benefit 38.00 lakh children and women through Supplementary Nutrition.
- Target to benefit 4.34 lakh women through PM Matru Vandana Yojana (PMMVY).
- Target to provide grant-based loans to 1,200 women under the Chief Minister Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana
- Target to connect with education 55,000 girls/women who have dropped out from schools/deprived of formal education under Kalibai Bhil Mahila Sambal Shiksha Setu Yojana.

Minority Development

- Target to benefit 2,998 Applicants under CM Anuprati Scheme.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

5. INDUSTRIAL, MINING AND ECONOMIC GROWTH



Provision of ₹2,088.97 crore for Petroleum Directorate which includes ₹2,088.68 crore from State fund for HPCL Rajasthan Refinery Ltd.

Provision of ₹2,423.95 crore for Industries Department which includes:

- ₹280.20 crore from State fund for Rajasthan Investment Promotion Scheme
- ₹663.00 crore from State fund for Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2019 and ₹296.43 crore from State fund for Investment Promotion Scheme, 2022.
- ₹300.00 crore State fund for Mukhyamantri Laghu Udhog Protsahan Yojana.



Provision of ₹48.02 crore from State fund for Mines & Geology Department.

Provision of ₹45.50 crore from State fund for Khadi and Gramodhyog Board.

Provision of ₹1,130.92 crore for Employment Department which includes:

- ₹825.64 crore for Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana.
- ₹250.00 crore for Rajasthan Skill Mission.



Important physical targets:

- To benefit 2,500 persons under Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Tribal Entrepreneurship Promotion Scheme.
- Regional Mineral Survey to be conducted in 1300 sq. km.
- Assistance to 2 lakh Graduate Unemployed Youth under Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana.
- To organize 175 employment assistance camps under the employment fair.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

6. TOURISM AND CULTURAL DEVELOPMENT



Provision of ₹255.29 crore from State fund for Tourism Department which includes:

- ₹120.00 crore for Tourism Information and Promotion.

Provision of ₹7.19 crore for Rajasthan Heritage Protection and Promotion Authority.

Devasthan Department



Provision of ₹160.77 crore for Devasthan Department which includes:

- ₹150.00 crore from State fund for Varistha Nagrik Tirth Yatra Yojana.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

7. CORE INFRASTRUCTURE

Energy



Provision of ₹41,941.50 crore for Energy Department which Includes:

- Provision of ₹29,432.39 crore from State fund for Power Tariff Subsidy.
- Provision of ₹10,789.12 crore from State fund to Discoms for Tariff Subsidy.



₹497.15 crore as Equity Support to Power Companies which includes:

- ₹300.00 crore from State fund for Vidhyut Vitran Nigam
- ₹97.15 crore from State fund for Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam
- ₹100.00 crore from State fund for Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam



Provision of ₹149.97 crore from State fund for Relief in Power Tariff to Agriculture Consumers.

Provision of ₹708.36 crore as grant for Reimbursement of Revenue deficit in Electricity Distribution.

Public Works



Provision of ₹15,078.05 crore for Public Works Department which includes:

- ₹5,000.00 crore from State fund for Rural Roads Construction.
- ₹1,650.00 crore from State fund under State Road Fund (SRF).
- ₹708.00 crore from State fund for NABARD assisted road works under RIDF.
- ₹500.00 crore from State fund for State Highways.
- ₹500.00 crore from State fund for Strengthening, Modernization and Widening of Major District Roads.
- ₹687.73 crore from State fund for Externally Aided Rajasthan State Highway Development Project (Phase-I ₹477.45 crore, Phase-II ₹210.28 crore).
- ₹1,302.00 crore (including State share ₹556.80 crore) for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).
- ₹400.00 crore from State fund for Atal Pragati Path.
- ₹1,200.00 crore under Central Road Infrastructure Fund (CRIF).
- ₹621.64 crore for Border Roads.
- ₹582.00 crore for Rajasthan State Highway Modernization Programme.

Transport



Provision of ₹1,319.43 crore for Transport Department which includes:

- ₹550.00 crore from State fund for Reimbursement of Free/Concessional Journey.
- ₹500.00 crore from State fund for Grant to RSRTC (including VGF).
- ₹150.00 crore from State fund for Environment and Pollution Management.
- ₹100.00 crore from State fund for Road Safety Fund.



Provision of ₹121.00 crore for Civil Aviation Department.



Important physical targets:

- Construction of 190 sub-stations (33/11 KV).
- Construction of 1,960 km 33 KV line.
- 5.49 Lakh New Electricity Connection.
- 1,30,830 General rural electrification works and new agricultural connections.
- Construction of 1918.60 circuit km (220 KV line).
- Construction of 30 sub-stations (220 KV).
- Construction of 2127.77 circuit km (132 KV line).
- Construction of 28 sub-stations (132 KV).
- Strengthening, Widening & Renewal of 1,715 Km State Highway/Major Districts Roads.
- Strengthening/Upgradation/Renewal of 9,235 Km. Rural Roads.
- Completion of construction work of 150 Atal Pragati Paths in 200 km.
- Strengthening/Upgradation/Renewal of 210 Km. Urban Roads.
- 2,500 km of roads will be constructed to connect 1,000 villages/habitations Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).
- To complete construction works of 11 ROB and 05 RUB.
- To complete construction works of 09 High Level Bridge (HLB).
- Target to benefit 14 Crore persons/passengers under free/concessional journey in RSRTC Buses (In Rajasthan Territory).
- Grant to 1,59,700 vehicles under the E-Vehicle Promotion Fund Scheme.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

8. WATER SECURITY AND RESILIENCE

Water Supply



Provision of ₹9,409.01 crore for Urban and Rural Water Supply Schemes which Includes:

- ₹970.80 crore from State fund for Re-organization/Extension of Urban Water Supply Project.
- ₹1,654.71 crore from State fund for providing FHTC under Jal Jeevan Mission through Retrofitting in major drinking water projects.
- ₹448.78 crore from State fund for Water Supply in SC habitation.
- ₹156.75 crore from State fund for Israda Dausa Project (Urban).
- ₹150.00 crore from State fund for Mukhya Mantri Jal Jeevan Mission (Urban).
- ₹572.00 crore from State fund for Upgradation and Re-organization under Jal Jeevan Mission.
- ₹400.00 crore for Rajasthan Rural Water Supply and Fluoride Mitigation Project Phase-II.



Provision of ₹7,808.32 crore for Irrigation & Flood Control which includes:

- ₹544.12 crore (including State share ₹408.09 crore) for Parwan Project.
- Provision of ₹559.62 crore from State fund for Minor Irrigation based on Solar Energy.
- ₹650.00 crore from State fund for Upper High Level Canal on Mahi Dam and ₹510.00 crore from State fund for Nangaliya Pickup Ware.
- ₹250.00 crore from State fund for Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area
- ₹327.15 crore from State fund for Water Harvesting Structures.
- Provision of ₹774.14 crore for Command Area Development (including ₹705.16 crore from State fund).
- Provision of ₹1,251.51 crore from State fund for Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner.
- Provision of ₹258.67 crore from State fund for Indira Gandhi Nahar Project, Jaisalmer.



Important Physical Targets:

- 15.31 lakh Functional Household Tap Connections (FHTCs) under Jal Jeevan Mission and other projects.
- Additional irrigation potential to be created in 74,040.31 hectares-
 - 46,894 hect. through Major Irrigation Projects.
 - 8,979 hect. through Medium Irrigation Projects.
 - 18,167.31 hect. through Minor Irrigation Projects.
- Target for construction of lined field channels in 1,10,696 Hectare

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

9. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CLIMATE RESILIENCE



Provision of ₹1,213.40 crore for Forest Department which includes:

- ₹231.35 crore from State fund for Regeneration of Degraded Forests.
- ₹241.72 crore from State fund for Rajasthan Forest & Bio-Diversity Development Project (RFBDP).
- ₹202.00 crore from State fund for Climate Change and Combating Desertification.
- ₹160.00 crore from State fund for Rajasthan Climate Change Response and Ecosystem Service Enhancement Scheme.



Provision of ₹3,317.00 crore for Disaster Management and Relief Department which includes:

- ₹1,778.00 crore (including State share of ₹444.50 crore) for State Disaster Relief Fund.
- ₹1,095.00 crore from State fund for Natural Calamities and Man-made Disaster Relief Fund.
- ₹444.00 crore (including State share of ₹111.00 crore) for State Disaster Mitigation Fund.



Important Physical Targets

- Plantation (forestry) works in 71,542 hectares area.
- Distribution of 605.00 lakh Plants under farm forestry.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

10. RURAL DEVELOPMENT



33,418.86 crore for Rural Development Sector which includes:

- ₹7,000.00 crore as Grants from State fund to PRIs under State Finance Commission.
- ₹6,750.00 crore (including State share of ₹2,753.12 crore) for Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission.
- ₹5,585.50 crore as Grants to PRIs under Central Finance Commission.
- ₹5,472.00 crore (including State share of ₹2,188.80 crore) for Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural).
- ₹1,445.00 crore for schemes being implemented under grant from Central Finance Commission.
- ₹1,410.00 crore from State fund for aid to Block and Mid Level Panchayats.
- ₹600.00 crore from State fund for Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan.
- ₹1,000.00 crore from State fund for MLA Local Area Development Scheme.
- ₹679.00 crore (including State share of ₹271.60 crore) for National Rural Livelihood Mission.
- ₹518.00 crore (including State share of ₹207.20 crore) for Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Watershed Component).
- ₹385.00 crore (including State share of ₹154.00 crore) for Swachh Bharat Mission (Rural).
- ₹261.00 crore from State fund for aid to Zila Parishad.
- ₹300.00 crore for Shyama Prasad Mukharjee Zila Utthan Yojana.
- ₹100.00 crore from State fund for Shri Annapurna Rasoi Yojana (Grameen).
- ₹61.00 crore for Mukhyamantri Rural Employment Guarantee Scheme.
- ₹50.00 crore for Magra Area Development Programme.
- ₹50.00 crore for Mewat Area Development Programme.



Important Physical Targets

- Construction of 80,000 IHHL and 4,000 Community Sanitary Complex (CSC) under Swachh Bharat Mission (G).
- 1.61 lakh Hectare Area to be treated under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana 2.0 (Watershed Component).
- Target to provide 5.85 crore Talis under Shri Annapurna Rasoi Yojana (G).
- Construction of 3 lakh houses under PMAY (G).

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

11. URBAN DEVELOPMENT



Provision of ₹20,323.61 crore for Housing & Urban Development Sector which includes:

- ₹3,860.12 crore from State fund as grant to ULBs on account of abolition of Octroi.
- Provision of ₹1,629.01 crore as grant to ULBs under Central Finance Commission.
- ₹2,286.02 crore from State fund as grant to ULBs under State Finance Commission.
- ₹6,765.66 crore (including State share of ₹4,528.11 crore) for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Mission-2.0.
- ₹812.66 crore from State fund for Rajasthan Urban Infrastructure Development Project.
- ₹1,414.48 crore from State fund for Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund.
- ₹500.00 crore from State fund for Maintenance/Renovation of ULB Roads.
- ₹1,289.25 crore (including State share of ₹660.58 crore) for Swachh Bharat Mission-2.0.
- ₹200.00 crore from State fund for Mukhyamantri Shahri Rojgar Guarantee Yojana.
- ₹684.11 crore for Pradhanmantri Aawas Yojana (Urban) which includes ₹273.64 crore from State fund.



Important Physical Targets

- Target to provide 9.75 crore Thalies under Shri Annapurna Rasoi Yojana (Urban).
- Target to provide employment to 2.36 lakh families under Mukhyamantri Shahri Rojgar Guarantee Yojana.
- Construction of 29,461 Toilets (IHHL) under Swachh Bharat Mission 2.0.
- Construction of 50,000 Houses Under Pradhanmantri Aawas Yojana (Urban).
- Laying of 3,486.79 Km. sewer lines and Construction of 31 New STPs of 212.35 MLD under AMRUT 2.0.
- To provide 4.27 lakh domestic sewer connections.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

12.EFFECTIVE GOVERNANCE AND PUBLIC SERVICES



Provision of ₹1,467.79 crore for Information Technology & Communication Department which includes:

- ₹101.50 crore from State fund for Rajeev Gandhi Fintech Digital Institute, Jodhpur.
- ₹150.00 crore from State fund for Command & Control Center.
- ₹289.00 crore from State fund for Rajnet.



Provision of ₹371.22 crore for Economic & Statistics Department which includes:

- ₹91.18 crore from State fund for Panch Gaurav Programme.



Provision of ₹519.94 crore for Law Department which includes ₹325.84 crore from State fund.

Provision of ₹556.16 crore for Police Department.

Provision of ₹139.38 crore for Home Guard Department.

Provision of ₹328.48 crore from State fund for General Administration Department.

SECTOR-WISE HIGHLIGHTS

13. FISCAL MANAGEMENT AND ECONOMIC POLICY



Provision of ₹214.08 crore for Commercial Tax Department which includes:

- ₹177.25 crore from State fund for subsidy under Rajasthan Investment Promotion Policy.



Provision of ₹12.37 crore from State fund for State Insurance & Provident Fund Department.

Provision of ₹ 138.42 crore from State fund for Treasuries & Accounts Department.
